and a conversion is taking place saying that the clarifications will be sought, in the form of a Short Duration discussion. I put on record my strong disapproval of the way in which things are being allowed to change. That is all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): This has been agreed to by the different party leaders for the benefit of the House.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Maybe, the party leaders did it. But it is the change that is taking place after two decisions that we made. That is all.

SHORT DURATION DISCUSSION ON IMPORT OF SUGAR

डा. मुरली मनोहर जोशी: (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस की शुरूआत करने के लिए आमन्त्रित किया है । चीनी के आयात के बारे में कल इस सदन में एक वक्तव्य भी दिया गया । मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्तव्य में न तो मुख्य समस्या की तरफ और न मुख्य मद्दे की तरफ कोई ध्यान दिया गया । यह कहा गया कि चीनी के उत्पादन में कमी हुई । 1991–92 में जितना उत्पादन हुआ था, 1992–93 में वह उत्पादन घटा और 1993–94 में उत्पादन और घट गया । अब चीनी का उत्पादन होने से पहले गन्ने का उत्पादन होता है और सरकार के पास एक बहुत अच्छा विभाग है जो गन्ने की फसल के बारे में आंकड़े देता है । सारी दुनियां जानती है कि महाराष्ट्र प्रदेश में सूखा पड़ा । महाराष्ट्र हिन्दुस्तान के बहुत बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में से है । उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार कम थी क्योंकि गन्ने की बुआई कम क्षेत्रफल में हुई । सारी दुनियां जानती है कि हिन्दुस्तान की आधी चीनी उत्तर प्रदेश में बनती है और इसलिए मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि किसी सरकार को 1993 की शुरूआत में ही इस बात का पता न लग गया हो कि 1993–94 में चीनी की भारी कमी होने की संभावना बढ़ रही है । मुझे यह भी सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखना है कि इस बारे में, अक्तूबर-नवम्बर, 1993 में तो कम से कम सरकार के सभी विभागों को यह बात पता लग गई थी कि चीनी के उत्पादन में बहुत कमी हुई । आपूर्ति मंत्रालय की ओर से बार-बार कहा जा रहा था कि चीनी का उत्पादन कम है, चीनी की सप्लाई कम होगी और इसलिए चीनी का आयात किया जाना चाहिए । केबिनेट कमैटी आन प्राईसेज की बैठकें हुई जिसमें बार-बार यह बात कही गई । 15 दिसम्बर की मीटिंग में मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस, सिविल सप्लाईज एंड फूड मिनिस्ट्री और इसके अलावा उनके कर्मचारी शामिल थे और उसमें फूड मिनिस्ट्री की तरफ से जो कहा गया वह यह कहा गया कि : "As per the latest estimates, the production of sugar was expected to be around Rs. 107 lakh tonnes in the year 1993-94."

यह बात कहना 15 दिसम्बर, के दिन, मैं समझता हू कि समस्या को जानबूझकर छिपाने के बराबर था । यह किसने कहा ? मंत्री महोदय ने खुद कहा या उनके अधिकारियों ने कहा, यह बात वहां कैसे कही गई, यह सवाल हम जानना चाहेंगे ? क्या कहीं यह कोशिश तो नहीं हो रही थी कि यह बताया जाए कि नहीं चीनी की कोई कमी नहीं है और लोगों को गुमराह किया जाए और एक आर्टिफिसल स्केअरसिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि वक्त आने पर फिर उसका फायदा उठाकर इस देश में घोटाले किए जाए, पैसे बनाए जाए और करोड़ों रुपए खाए जाएं और उसके बाद यह भी कहा गया कि : "In view of the likely increase in production, the Ministry felt that there was no case for anxiety and that the situation would be monitored carefully."

मिनिस्ट्री आफ सिविल सप्लाई ने इस बात से असहमति व्यक्त की थी और यह कहा गया कि चीनी के दाम बहुत बढ़ेंगे, चीनी की कमी है और इसलिए आयात होनी चाहिए । लेकिन फूड मिनिस्ट्री इस पर पर्दा डाले बैठी रही । उसके बाद फिर यह कहा जाता है कि मिनिस्ट्री आफ फूड ने यह बात बार-बार कही कि हिन्दुस्तान में चीनी की कीमतें सबसे कम हैं । अब यह बात जरा गौर करने

डा. मुरली मनोहर जोशी :

की बात है। फूड मिनिस्ट्री का आकल यह है कि दुनियां भर में हिन्दुस्तान में चीनी की कीमतें कम हैं और इसलिए कोई जरूरत नहीं है चीनी के दाम घटाने की और कंज्यूमर को पैम्पर करने की। और कंज्यूमर को पेंपर करने की जरूरत नहीं है, उपभोक्ता की खुशामद करने की जरूरत नहीं है या उसकी भलाई करने की कोई जरुरत नहीं है। इसलिए अगर चीनी का दाम बढता है तो बढने दो क्योंकि हिन्दुस्तान में चीनी का दाम सबसे कम है। यह प्राइसेज के ग्लोगलाइजेशन का नतीजा है। घोटालों का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की और जरुरत पड़ेगी तो सितम्बर 1994 तक जरूरत पड़ेगी जब चीनी की कमी होगी, तब तक के लिए हमारे पास काफी स्टॉक है और हम तब इंपोर्ट कर लेंगे।

अब बंगलिंग किस तरीके से हुई, वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, 15 जनवरी को फूड मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट के अनुरोध को टर्न-डाउन किया लेकिन 21 जनवरी को इजाजत दे दी जब कि सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री ने शॉर्टेज की बात कही। अब 29 जनवरी से 9 माच तक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेज ने फैसला करने की बात कही कि इंपोर्ट करना चाहिए अथवा नहीं और इस कमेटी की मीटिंग 5–6 दफा पोस्टपोन की गई लेकिन इसके बाद 9 मार्च को डिसीजन एनाऊंस हुआ। बाद में 18 से 28 अप्रैल तक प्रधान मंत्री के मंत्रालय से और सेक्रेटरीज की कमेटी से दिशा मिलती है कि एस.टी.सी. और एम-एम-टीसी. आयात करें, वह भी आयात नहीं करते। बाद में 13 से 16 मई के बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी आलोचना करते हैं कि कामर्स मिनिस्ट्री ने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि एस०टी०सी० और एम.एम.टी.सी उनके अतर्गत हैं। अब 21 मई से 24 मई तक अफसरशाही के बीच में झगड़ा होता है कि किसने आयात में देरी की। इसके लिए वे एक-दूसरे पर ब्लेम्म लगाते हैं और 7 जून को पी.ए.सी. इस बारे में कहती है कि जो घोटाला हुआ, इसके बारे में जांच की जाए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सारे घोटाले के अंदर, इस तमाम देरी के अंदर जो नीति अपनाई गई, उसका नतीजा क्या हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में इंपोर्ट की कीमतें किस तरह से बढीं। फरवरी 22 को 294 डालर प्रति टन कीमत थी और 9 मार्च को यह बढ़कर 327 डालर प्रति टन हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यह मई माह के शिपमेंट्स के लिए कीमत थी, जो चीनी मई माह में आनी थी। अगस्त के लिए जो फारवर्ड रेट किया जा रहा था, उसका दाम बढ गया और आम आज एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. 350 डालर प्रति टन पर आयात कर रहे हैं। अगर हिन्दुस्तान में 10 लाख टन चीनी का आयात करना है तो इसका मतलब है कि एक हजार लाख करोड़, इतने मूल्य की चीनी आयात करनी है और अगर एक किलोग्राम पर 4 रुपये का भी मुनाफा उठाया जाए तो 4 हजार करोड़ रुपए का घाटाला तो सामान्य तौर पर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीनी के दाम थोक दाम किस रफ्तार से बढे हैं। मई, 1993 में चीनी का दाम 11.25 रुपए प्रति किलो था और आज मई, 1994 में यह 16.50 रुपए हो गया है और गांव तक पहुंचते-पहुंचते तो यह शायद 19 रुपए प्रति किलो हो जाएगा।

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय जोशी जी, कल खान मार्केट से मैं 20 रुपए प्रति किलो की दर पर चीनी लाया हूं तो गांव की बात तो छोड़ दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : तो इसका मतलब है कि गांव में पहुंचते-पहुंचते तो वह 22 रुपए प्रति किलो हो जाएगी।

SHRI V. NARAYANASAMY: Where did you buy from?

SHRI SOM PAL: From Khan Market.

डा. मुरली मनोहर जोशी : गांव तक पहुंचते-पहुंचते इसका दाम 22–24 रुपए किलो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 11.25 रुपए के बदले 24 रुपए का दाम देना पड़ेगा। तो आज यह दाम हिंदुस्तान के उपभोक्ता को देना पड़ रहा है और हमारे खाद्य मंत्री कहते हैं कि उपभोक्ता

नहीं करनी चाहिए, उपभोक्ता को पेंपर नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। तो किसका ध्यान रखा जाना चाहिए, उन लोगों का जिन्हें आयात लाइसेंस दिए गए हैं ? अगर आप उपभोक्ता का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका ध्यान रखेंगे.. (**व्यवधान**) इंटरनेशनल स्टेंडर्ड पर सब को चीनी दी जाए, हिन्दुस्तान में चीनी के दाम अंतर्राष्ट्रीय दाम न हो, हिन्दुस्तान में चीनी 22, 23 और 24 रुपए बेची जाए, तो यह मनाफा कहा जा रहा है ? मेरा आरोप है कि यह चीनी का घोटाला जानबूझकर किया गया है। चीनी का घोटाला जब चुनाव होते हैं तो किया जाता है। 1967 में भी और 1972 में भी चीनी का घोटाला हुआ था मिसेज गांधी के जमाने में चीनी और सीमेंट के घोटाले होते थे।

श्री मूल चन्द मीणा : 1979 में क्या हुआ था ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : 1979 में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्राइस स्टेबिलिटी थी.... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : 1979 में लोग राशन कार्ड भी भूल गए थे। सवा दो रुपए किलो चीनी मिलती थी।..... (**व्यवधान**)...

डा० मुरली मनोहर जोशी : सच को सुनने की और बर्दास्त करने की ताकत चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : 1979 में चीनी की उपलब्धता का हाल था कि कबाड़ी जो पुरानी चप्पलें, फटे जूते, पुराने डिब्बे को एक तरफ रखकर चीनी बेचते थे। यह स्थिति थी चीनी की।.... (**व्यवधान**)

डा० मुरली मनोहर जोशी : आपने जो आयात किया है वह ड्यूटी फ्री आयात किया है। यह ड्यूटी फ्री आयात आप करते और उस के बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वह चीनी आती जो मुझे खुशी होती। लेकिन ड्यूटी फ्री आयात की सुविधा उन तमाम लोगों को दी जो मुनाफाखोरी करते हैं। यह शर्त आप ने नहीं रखी थी कि जो चीनी आयात करेंगे वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए लेवी देंगे : आप ने ओपन जनरल लाइसेंस में ड्यूटी फ्री चीनी आयात करने के लिए लाइसेंस किसको दिए, यह मैं जानना चाहता हूं। कामर्स मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा कि चीनी का आयात करने के लिए आप ने लाइसेंस किसको दिए हैं ? मैं आप को बताता हूं कि पी०एम०ओ० आफिस के लोगों के रिश्तेदारों को लाइसेंस दिए गए, उन लोगों को जो प्रधान मंत्री के निकटस्थ हैं, उन को लाइसेंस दिए गए हैं। मैं जानना चाहुंगा कि ये लाइसेंस किसको दिए गए..... (**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Let him speak मंत्री जी जवाब दे देंगे।... (**व्यवधान**)..

SHRI V. NARAYANASAMY: No, Sir. That is a different matter. He is making an allegation.

डा० मुरली मनोहर जोशी : अनरजिस्टर्ड लोगों को लाइसेंस दिए गए (**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am on a point of order. The hon. Member, while speaking, was referring to the Prime Minister. (*Interruptions*). Kindly hear me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Kindly sit down. He has not referred to the Prime Minister. He said PMO.

SHRI V. NARAYANASAMY. He has referred to the Prime Minister.

DR MURLI MANOHAR JOSHI: I am not referring to the Prime Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): He has referred to PMO.

SHRI V. NARAYANASAMY: He cannot say that and get away with that. He is a senior Member of this House. When he makes an allegation he has to substantiate it before this House. If

[Shri V. Narayanasamy]

he is not able to substantiate it, let him say that.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I am on a point of order. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I want this to be answered by you now.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I am on a point of order. If the hon. Member has levelled an allegation about the relatives of the Prime Minister, our Food Minister is here to defend the Prime Minister. Let him defend. Whether he wants to defend and whether there is material to defend, that is a different matter.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I referred to a news item in the 'Statesman ofJune, 13—Sugar muddle; it says:

> "One aspect of the sugar muddle that has yet to be touched upon is the large number of licences given to those who are said to be wielding enormous power. There is, for instance, the case of a relation of the highest in the land securing two licences in Andhra Pradesh. A minor functionary in the highest office is also said to have been given a licence, while will-connected industrialists who are known to be close to the ruling party have been obliged."

This is the 'Statesman' of 13th June.

श्री एस० एस० अहलुवालिया :आप ने जो वक्तव्य रखा है और जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं उन दोनों में फर्क है। एक तरफ प्रधान मंत्री का नाम लेते हैं... (**व्यवधान**) या तो आप उस को सर्टेसिशेट कीजिए या ... (**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Member should not quote from a newspaper item. And unsubstantiated allegations should not be levelled by Members.

डा० मुरली मनोहर जोशी :आप कृपा करके चुप रहिए.. ((**व्यवधान**)..

There is no contradiction here.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) मिनिस्टर साहब जवाब देंगे इनको क्या परेशानी है । .. (**व्यवधान**)..

डा० मुरली मनोहर जोशी : कल और इसके पहले हमारे खाद्य मंत्री ने यह कहा था, इनका बयान है इस संसद के अंदर ... (**व्यवधान**)...

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उन्होंने इसके पहले जो कुछ कहा.. (**व्यवधान**) कैसे रिकार्ड में जायेगा ?.. (**व्यवधान**)..

डा० मुरली मनोहर जोशी : आपका रिकार्ड स्टेट हो गया, प्रधान मंत्री को पता लग गया .. (**व्यवधान**)..

SHRI V. NARAYANASAMY: He can't make a wild allegation.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I have made no allegation. I have quoted from the newspaper.

SHRI V. NARAYANASAMY: Let him prove it. He has made allegations against the Prime Minister and his family.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: This is how the news is going in the country ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: He is a senior Member. He should know how to... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You have made your submission. Please sit down, Mr. Narayanasamy...(*Interruptions*)... Nothing will go on record...(*Interruptions*)... Nothing is going on record... (*Interrup-*

tions)... Mr. Gautam, please sit down. I will check the record. It such a remark is there, naturally I will take a decision. Please sit down.

SHRI V. NARAYANASAMY: I raised a point of order. I wanted a ruling on that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): It is all right. Please sit down. Now, Dr. Joshi, there are four people in your party.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: But they should not disturb me. This is not my time. It is their time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): In any case, please spare some time for them!

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं आप से यह निवेदन कर रहा था खाद्य मंत्री जी ने कल यह कहा संसद के दूसरे सदन में और वह बयान अखबारों में भी छपा है पूरे तौर पर कि उन्होंने शत प्रतिशत आदेश प्रधान मंत्री का पालन किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने उन्हें क्या आदेश दिये थे और उन्होंने किस हद तक उसका पालन किया क्या उन्होंने यह आदेश दिया था कि टेंडर की तारीख खुली रखें? क्या उन्होंने यह आदेश दिया था कि चीनी आयात मत कराने दें? क्या उन्होंने यह आदेश दिया था कि चीनी के अंतर्राष्ट्रीय दाम और भारत के दाम में इतना फर्क करो? क्या उन्होंने यह आदेश दिया था कि लाइसेंस इतने लोगों को दिया जाए? आपने कल यह भी कहा था और एक शेर भी पढ़ा था :

हम करें क्या दरिया अगर लबरेज मैखाने में है,

हम तो इतनी जानते जितनी पैमाने में है।

आपके पैमाने में जितना है उतना आप जानते हैं लेकिन औरों के पैमाने में कितना है वह भी बताइये। कौन-कौन मैखाने में हाजिर थे यह भी बताइये। दरिया कितनी लबरेज है, कितनी ऊंचाई है या यह भी बताइये। एक हजार करोड़ दो हजार करोड़, तीन हजार करोड़, 4 हजार करोड़ कितना लाया, यह भी बताइये। मेरा आरोप है कि यह घोटाला चीनी का हिन्दुस्तान की आजादी के बाद तमाम घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले ने हिन्दुस्तान के उपभोक्ता को चूस लिया। एट द कास्ट आफ पुअर कज्यूमर। आपने हिन्दुस्तान के तमाम लोगों का नुकसान किया है। आपने अपनी पार्टी के लिए चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा किया है आपने अपने तमाम लोगों को पुरस्कृत किया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता और मेरा एक सवाल है खाद्य मंत्री जी से कि वह अपना त्यागपत्र कब दे रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Member of the BJP was accusing the Government for the import of sugar and he said that there was delay in the import.

The real position was that at the time when they were assessing the situation about the sugar production in the country, they found that the sugar production was 240 lakh tonnes which was more than that in the previous year which was 231 lakh tonnes. What happened was that in States like Maharashtra and Uttar Pradesh some of the sugarcane was diverted for production of Khandsari and gur. The production of sugar was estimated to be 107 lakh tonnes which could not be reached, and it came down to 96 lakh tonnes only. The Government had a buffer-stock of 31 lakh tonnes. The total requirement of the country for this year was estimated to be 124 lakh tonnes. When we consider that, we have sufficient sugar to meet the demand. But, then, suddenly the sugar production was reduced... (*Interruptions*)...

Kindly hear me. The sugar production was reduced because of the diversion of sugarcane by the farmers for production of gur and khandsari in Maharashtra and U. P. especially.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: What is the percentage of diversion?

SHRI V. NARAYANASAMY: The Minister will tell you that.

Therefore, it necessitated maintenance of the buffer stock. Also, normally the sugar industry starts production of sugar right from October or November. The period from May to June or July is a lean period, and no sugar production will be there, and the existing sugar with the Government and also with the sugar industry has to be released. The Government of India took the decision to import sugar in the month of March because various procedures for the purpose of its import have to be followed and it was contracted in May.

Sir, now that sugar has been imported, there is going to be a declining trend in the price of sugar in the market. Actually, I would like to submit that especially in U.P., sugar was sold at Rs. 16.50 per kg., and now it is being sold at Rs. 16 only. More sugar is coming from abroad either through the Government organisations or through the private agencies who have been given the O.G.L. to import sugar. Sugar has started coming, and it is going to be in the market. Actually, according to the estimate, 13 lakh tonnes was estimated to be imported. It has been contracted also. The Government's share is reported to be seven lakh tonnes. The sugar has already come, and it is going to be distributed to the people.

Take the case of Mauritius which is one of the major sugar-producing countries. Mauritius produces sugar for the international market. That is the only source of livelihood for the whole country. That country's sugar production has come down to 50 per cent of its normal production. Take the case of Brazil. Its production of sugar has come down to 60 per cent. The sugar production of the world as a whole has come down... (*Interruptions*)

Mr. Jaipal Reddy kindly here me.

Therefore, the price of sugar in the international market started shooting up. That is quite natural. If the demand is more than the availability of sugar, or any other commodity, in the international market, its price will always shoot up. Therefore, there is nothing to be hidden in this case.

The senior Member was accusing the Congress Government. He was accusing the Prime Minister's family. All these are wild allegations.

3.00 P.M.

Let them come before the House and substantiate the allegations which they have made in this House. Let the people of his country not feel that there has been something fishy in that. They have been surviving on that plea raising false allegations and false bogey. These political leaders of the Janta Dal and the BJP are surviving in this country on this. Let them show even an iota of truth of this in the import of sugar. Dr. Murli Manohar Joshi just by reading a newspaper item considers, that the allegations are proved. Hon. Member, Som Pal, is telling that they have been able to get one metric tonne of sugar at $225. But, he has not said what quality of sugar has to be contracted. There are various qualities of sugar. Sugar may be available even at $200 per metric tonne, but are you going to buy inferior quality of sugar? In the international market it is going to be there. Therefore, Sir, there is no hanky-panky in this. Let them not make a false allegation and mislead the people. When there is a demand, we are going to import sugar. It is the money of the Government. The private parties would like to import and sell it in the market. Let them sell. But one thing they would like to appreciate that they are not getting it. In the PDS the price of sugar is Rs. 9.15...

SHRI SOM PAL: It is neither available, nor is it sold at this price. It is entirely wrong.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is so because all the sugar Delhi Government through the blackmarketeers. They are not preventing the blackmarketeers and the hoarders of sugar from hoarding so that it is available to the people. On the other hand they are just saying that it is not available. Even Dr. Murli Manohar Joshi, whose house is in Delhi and whose party Government is in Delhi, is saying that sugar is selling at Rs. 20 per kilogram in the open market. His party Members are also saying that. Now, what has happened to the public distribution system in Delhi? The Delhi Government is to be squarely blamed for it. Therefore, Sir, the Government has to take a conscious decision to import sugar to meet the demand for sugar and to see that the PDS is not affected. It is time for all the political leaders to see that PDS functions effectively in this country. That they are not doing. Let us all sit together and see that the people, who are eligible to get the retioned items, get it. But hoarding and blackmarketing are being encouraged. Why are they encouraging it? The people who are entitled to get it under the PDS, are not getting it. They are crying. Therefore, I would like to submit to the hon. House that for political reasons, they should not make false allegations. If they make allegations, they must substantiate. This is not the platform to level allegations without substantiating them. Therefore, Sir, since the import has been made, the situation has eased. As the sugar has come, its prices are showing a downward trend. So, there is no panic about its shortage. Let them tell the people about that. They should also see that the public distribution system functions effectively. We need their cooperation in this field. With these words, I conclude.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, before I participate in the discussion, let me place my protest on record. We said yesterday that the matter concerns the Prime Minister's Office, the Cabinet Secretariat, the Food Ministry, the Civil Supplies Ministry, the Commerce Ministry and the Finance Ministry. Therefore, this question should only be answered and can only be answered competently and comprehensively by the Prime Minister.

Our Prime Minister, of course, has a flair for performing a vanishing act. Whenever there is a crisis, his first reaction is to go underground. That is what he has done on this occasion.

Sir, I am unable to understand a new phrase that has come into wide circulation. The phrase is "Prime Minister's Office". I have scanned all the provisions of the Constitution, all the pages of the Constitution, but have never come across this word. What is this PMO, this extra Constitutional authority? What is its role? It appears to be playing a role behind everything ranging from foreign policy to food policy. It is exercising an authority without taking any responsibility.

Now coming to this, it is interesting to know that it is both a muddle and a scandal. Even as a muddle, it is a scandal. The sheer ineptitude, incompetence involved in the management of this problem is nothing less than a scandal. Then, as a scandal, it is monumental, it is multi-dimensional. Why did a scandal assume this kind of an ugly public character? I would like to tell Dr. Joshi that he was wrong when he said that they took money for their party. If they had taken money for their party, then, all this scandal would have never become public. Thieves have fallen out because quarrel arose sharing of the money. So, I would like to differ from Dr. Joshi. The Congress party is completely innocent, Congress Ministers are guilty.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, can this be allowed?

SOME HON. MEMBERS: Why not?

SHRI V. NARAYANASAMY: He is making wild allegations against Congress Ministers.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: He says that... (*Interruptions*)... guilty cannot be allowed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I object to what he has stated. He just cannot stand up and make a bold statement that all the Ministers have made money out of this... (*Interruptions*)... He has to prove it before he makes such a statement .. (*Interruptions*)... He is a responsible member of his party. He should know how to talk on such an issue. . (*Interruptions*).. This is not the way. . (*Interruptions*)... I do not think... (*Interruptions*). . take it very seriously.

श्री सीमपाल: सरकार की चार हजार से आठ हजार करोड़ लाने की अनुमति हो सकती है लेकिन अगर विपक्ष इस बात के लिए आवाज उठाए तो उसकी इसकी अनुमति नही है ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, I never said that all Congress Ministers are guilty.

SHRIMATI MARGARET ALVA: You said that.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I implied that some Ministers are guilty. For example. I can tell you that Mr. Antony is not guilty... (*Interruptions*)... I can tell you who are not guilty. But I do not know who are guilty... (*Interruptions*) .. Now let me go to the next point.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Reddy is speaking without knowing anything. .. (Interruptions).

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, is it a new scandal? It is, in fact, a classic repetition, though of a ridiculous and, farcical kind, of the 1989 scandal. The scale has been enlarged. Of the *dramatis personae* are divided. At that time, they were all united. That is the only difference. What are the common features of these two scandals? In 1989 it was leaked out that India would go in for massive import. This leakage was accompained by delay in imports. This double function of leakage and delay led to inevitable rise in the international price of sugar. Now, naturally, the country had to pay more through its nose. In 1989 also unregistered firms were entertained. In 1989 also, the Public Accounts Committee went into the matter. All these elements are present in today's tragedy as well. Now, I am on the 1989 scandal. To the best of my knowledge, the National Front Government ordered a CBI inquiry into the 1989 scandal. Would the Food Minister of Mrs Margaret Alva, who is dealing with the CBI, take the House into confidence and throw light on what happened in the CBI inquiry? Who has been found guilty by the CBI? Why has the report been not made public? Why have the guilty not been prosecuted and punished? Why are you suppressing information? Why are you withholding it from this House?... (*Interruptions*).

Now, I am coming to drama No. 2, that is, 1994. It was clear, way back in November... (*Interruptions*).

SHRI S. S. AHLUWALIA. In 1990, V. P. Singh was the Prime Minister of the country and the CBI inquiry was constituted by him. Why has he not disclosed this information to this House? (*Interruptions*)...

एक माननीय सदस्य : आप लोग.... (**व्यवधान**)...बोफोर्स...(**व्यवधान**)

श्री एस० एस० अहलूवालिया: बैठिए बैठ जाएं ।...(**व्यवधान**)...15 दिन में देंगे ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : वी.पी. सिंह ने कहा ...(**व्यवधान**)...जेब क्या हो गई उनकी ...(**व्यवधान**)...जेब में ही हैं बोफोर्स के पैसे...((**व्यवधान**)..

श्री एस० एस० अहलुवालिया : वह तो एकाउंट का नंबर लेकर घूमता था । कहा है वह अभी बताएं जरा ? ..(**व्यवधान**')..

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, I must express my deep debt of gratitude to Mr. Ahluwalia. He raised a very relevant question. The N. F. Government ordered a CBI inquiry into it. Before the N. F. Government laid down office, the inquiry had not been completed. (*Interruptions*) I am telling you this. If it is wrong, Madam, you are the repository of governmental truth and therefore, you should be able to take us into confidence. To the best of my knowledge, I am stating the facts. If I am wrong, I would welcome any correction from the omniscient Margaret Alva. (*Interruptions*).

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am glad that you admit that at least.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, in November 1993, the Government kenw full well that Indsa would have to import more than one million tonnes of sugar. It knew it. Then why this dabbling delay? It is simple. Mr. Kalp Nath Rai is a very popular man. He is very popular among the members, distinguished members, of the Indian Sugar Mills Association. He is very popular because he is a supporter-of the producer as against the consumer. So there is a big fight going on between Mr. Kalp Nath Rai and Mr. Antony. Mr. Antony is supposed to be crusading for the consumer and Mr. Kalp Nath Rai is supposed to be fighting for the producer. And, since producers do not have an association and only millers have an association, our Minister, Mr. Kalp Nath Rai is a hot favourite, pet, of this ISMA. It is another matter that the ESMA must be applied against those who are pets of the ISMA. Now, I would like to know what the Cabinet Committee did. We have a Cabinet Committee on Prices. Was it sleeping over it? I am told that the Finance Minister said that the sugar price issue would go out of control. Did he say that? If so, when? Why was this warning ignored? I know, our Minister would tell us that we permitted imports through OGL. Did not the Government know that our private bodies were such as not to be able to import massive quantities through OGL? They knew. It was a deliberate device to delay the process of imports. And then, our Prime Minister's Office woke up from its deep slumber. On 14th May, the P. M. was leaving for his all-important talks with Bill Clinton in White House. Just before he left, he did not have much time. He left instructions. With what? With again, that intangible quantity known as PMO. And the next day, the Cabinet Secretary told the Food Secretary. And our Food Minister is a very popular man in U. P. Therefore, he was campaigning in by elections and the matter was urgent; it could not brook delay, the Food Minister had to be ignored, the Food Secretary had to act. After all, the Food Secretary and the Cabinet Secretary were acting in the interest of the nation. So, the Minister needed to be ignored. And they said, "All offers must be received in 24 hours." And the Food Minister cancelled that order. I somehow find it difficult to blame him for cancelling order because his public explanation is that he did because of a report submitted by the PAC which was heeded by none other than the redoubtable Vajpayee. It said, "These imports must be handled by the STC, not by the FCI.' At any rate,—even if the Food Secretary, and the Cabinet Secretary were prompted by the noblest of motives in the world, they had no business to ignore the Minister—If the Minister was bad, the Minister should be dismissed, if the Food Secretary is mad, he should at least be transferred. But then, the bad Ministers remain, the mad Secretaries remain, the Government goes on and we only keep on talking over here. Then why did the STC, the MMTC, which were also authorised to import through OGL, failed to import? We were told, they were bogged down in the morass of subsidy question.

SHRI E. BALANANDAN: Molasses.

SHRI S. JAIPAL REDDY: He is referring to molasses. He has unfortunately a long memory when our Minister passed an order to decontrol molasses, that was another measure

(SHRI PRANAB MUKHERJEE): The which endeared him to ISMA. That is another matter. I do not want to go into that.

The question, therefore, is: Why did the STC and the MMTC fail to import? Why did the Finance Ministry fail to settle this question of subsidy in time? Or was the STC a privy to the process of delaying imports? One coincidence is, that the present Commerce Secretary was earlier a Food Secretary and as Food Secretary he was a buddy of our food Minister. This is only a coincidence. I do not read too much into all this but I should refer to coincidences. ...(*interruptions*). Now we are told that the MMTC and the STC are importing on a big scale. There is a difference again between the rate at which the MMTC imported and the rate at which the STC imported. How can there be a difference when the arrivals of imports of both the Corporations are at the same time. They are to come in October. Why is there a difference?

Mr. Vice-Chairman, now the Indian sugar lobby has made a killing, a neat, silent killing, of Rs. 1,000 crores. Now, I would like to know who has got what cut in this killing. In the last four or five months the price of sugar in the world market has gone up by 120 dollars per tonne and for 12 lakh tonnes, which you are importing, it would mean a loss of Rs. 600 crores to Rs. 700 crores in foreign exchange. The Commerce Secretary said that in an interview the Cabinet Secretary told him to entertain the offer of unregistered firms including one foreign firm, Macdaniella. Is it true? The Commerce Secretary alleged that the minutes of record were changed by the Cabinet Secretariat. Is it true? Who is competent to answer these allegations of the Commerce Secretary? I, therefore, believe that the Prime Minister should come forward to answer all these questions. If he runs away from the House, this scandal will haunt him. (*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI: We take strong objection to this. He is not running away from the House. (*Interruptions*).

SHRI S. JAIPAL REDDY: I amend my expression. He is keeping away from the House deliberately. (*Interruptions*)...

SHRI SATCHIDANANDA: Sir, 'deliberately' is also not correct. (*Interruptions*)...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Therefore, this entire Government is under a cloud. I have got great faith in Mr. Kalp Nath Rai in one respect. He may be anything. But he is also capable of being devastatingly frank. So many people are trying to silence him I don't want him to be silent. Today I want him to break his silence. Anyway, his reputation is in the mud. So, you have nothing to lose, Mr. Kalp Nath Rai. Come and break your silence.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Shivajirao Giridhar Patil. (*Interruptions*)...

SHRI JAGESH DESAI: Yesterday he was saying that Mr. Kalp Nath Rai was the accused. (*Interruptions*). ..

SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me an opportunity to speak on this very important subject. Sir, I have very patiently listened to the speeches of hon. Shri Murli Manohar Joshi and hon. Shri Reddy. I am sorry to state that instead of trying to understand the very serious nature of this issue, they have been making speeches on he peripheral issues, trying to find a scandal and trying to make accusations without any proof. We have been experiencing this kind of a situation in this country for the last ten years. Let me tell this august House that India has earned a very dubious distinction of being a country which produces large quantities of cane, and being the biggest producer of sugar and

also of being the biggest importer for many years. For seven years, between 1982 and 1990, we had to resord to imports and the total imports in that decade was, Mr. Vice-Chairman, of the order of a little less than 4 million tonnes and during that time the foreign exchange situation was very bad. This happened because of the peculiar nature of sugar production and every two or three years we experience this sugar cycle. As the hon. Minister has stated in his statement, sugar production in the country came down from 134 lakh tonnes in 1991-92 to 106 lakh tonnes in 1992-93 season. It came down by about 28 lakh tonnes. (*Interruptions*). I am not yielding the floor. You must have heard me wrong. So, this peculiar phenomenon happened due to so many factors. If happens again and again. It will happen again and again if we don't address this problem with all seriousness considering the situation that we require six lakh tonnes of more sugar every year for the growing population and demand. That is why this august House must consider this situation from the point of view of the production of sugar. Why did it go down? It is true that the Government, the industries and also the people thought that this year the production of sugar would be 106 lakh tonnes to 107 lakh tonnes. In fact, some people thought that it would be 110 lakh tonnes. Let me tell this august House that the Minister of Food and the Department of Food have been very carefully monitoring the situation. They are meeting the farmers and the organisers very often and trying to understand how the situation is developing.

Dr. Murli Manohar Joshi made a comment that they knew that the production of sugar was going to be less in October. Let me inform this House that till the end of December the total production of sugar in this country was two lakh tonnes more than last year. This upward trend was for the obvious reason that the situation in UP was looking very bright. But, in Maharashtra the situation was bad. It was not improving. When we tried to take stock of the situation in Maharashtra, we came to the conclusion that we could reach to about 30 lakh tonnes. We hoped that sugar production in UP could be 35 lakh tonnes to 36 lakh tonnes. This was something which did not prove correct and that must be taken into account. So, every effort was made. As far as my information goes—it may be wrong—the Food Ministry prepared a note as early as in January and sent it to the Cabinet Secretariat. It was decided in January thtt import should be made. In fact, the people who were concerned with the import and export of sugar met the hon. Minister of Commerce to allow them to import raw sugar to process it in white sugar here so that they need not touch the domestic sugar for export. I am glad to say that Mr. Pranab Mukherjee and his Ministry were very quick in giving this permission. When the question of import came, we did suggest to the Commerce Minister to import only through STC/MMTC. I think, Mr. Pranab Mukherjee knew that this particular situation might be misunderstood. He categorically said, "No". He said, "If sugar has to be imported, I want that it should be imported through OGL so that everbody has freedom. That would raise competition in India and nobody would say that there has been something fishy." I think that was the correct approach. If he were to give the particular authority to some particular organisations, then this misunderstanding could have been of greater dimensions. Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Joshi Saheb said that the sugarcane production in Uttar PPradesh was less. I am saying, "No, Sir. It was much better. In fact, we were depending very much tion in Uttar Pradesh was less. I am sugar factories in Uttar Praesh are doing much better. But, unfortunately, spite of all the efforts of the Minister of Food in persuading the Uttar Pradesh Government to do somethin nothing has been done. This is something which this House, the Government and the people must serious

think of. A very large amount of sugarcane today is being diverted to jaggery and khandsari. Jaggery is the traditional production and we cannot do anything about to stop it. But there are more than 1,000 units producing khandsari. What do they do? Joggery and Khandsari draw 65 per cent of sugar of Uttar Pradesh from out of which they can thrdly extract 65 per cent to sugar Thirty five per cent of sugarcane is being wasted and burnt in the production of Khandsari and only 35 per cent of sugarcane comes to the factories in Uttar Pradesh... (*Interruptions*).

SHRI SOM PAL: But who is to be blamed for it? (*Interruptions*). Why don't you allow the khandsari units to function? You are not giving them licences...(*Interruptions*) We have been asking for the past five years for delicensing... (*Interruptions*).

श्री भूपे द्र सिंह मान : खांडसारी को ओपन क्यों नहीं कर देते ;

SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL: When India requires that much of more sugar this question assumes importance. Sugar and khandsari are not on an equal ground. Khandsari has no taxes. There is no purchase tax on it. The units do not pay anything. When the availability of sugar is so less, why allow them to waste sugar. So, when India is going to need so much of sugar, the Government will have to consider it seriously. I am glad to note that the hon. Food Minister has already made a request to the Government.

Coming to the point, the situation has been monitored almost every 15 days. The Food Secretary, the Joint Secretary and the industry tried to take stock of the situation and essential steps were taken. As far as the import of sugar is concerned, in the last 25 years, perhaps, in the last 30 years, no other organisation has had the experience of importing sugar except the STC. The STC was also doing it with the help of ISIEC. I had requested the hon. Minister of Commerce to give permission to it but he rightly denied it. When the OGL was started, there was talk of cheap sugar. I may tell you, Mr. Vice-Cahirman, Sir that, I, as the Vice-Chairman of the Corporation, have six proposals pending with us ranging from $218 per tonne to $298 per tonne. But I must also tell you that no positive clue of the goods has come, no confirmation of the bank has come and when we are supposed to open an L/C, they are willing to open two per cent of bond. They are not able to tell us who the person is who is dealing in the bank, they are not able to tell us where the source is. When we send our inspectors, they don't find the goods and we cannot risk Rs. 150 crores or Rs. 170 crores in such an unreliable situation. It is very good to say

सस्ता मिल रहा है, हमको नहीं मिला तीन महीनों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।

There are faxes after faxes, telephones after telephone. But when we ask for confirmation, it does not come. Let anybody, including the hon. Member who it is a very diffecult and a different situahas said about it, give us the proof. So, Reddy was all peripheral, not touching the issue. Now, the hon. Joshi Saheb, who is the hon. leader of his party, says that Mr. Kalp Nath Rai is the friend of producers only. Sir, the Minister has consistently been saying that he would like to protect the interests of the farmers, he would like to protect the interests of the consumers as well as of the industry. We will have to have sugar. But if you want to do away with this type of dubious distinction which I described, then you will have to have your own sugar. If you want to have your own Sugar, you have to protect the interests of the farmers and the Industry.

But what is the situation on the ground? Have you ever tried to know this? Joshji accused Kalp Nathji of making money by saying that in India

sugar was always the cheapest item. Yes, I claim that in the whole world India is the only country where sugar is sold at the cheapest rate. Let me tell you that that misconception will have to be done away will sometime. When a sugar factory is required to pay Rs. 750|- per tonne of sugar cane, how do you expect sugar to be available at Rs. 12|- a kilogram? It is not possible. When we take away 40 per cent of sugar at less than the break even price and that particular loss being passed on to the remaining 60 per cent sugar, sugar can never be very cheap.

Rajivji brought about a change in this policy in 1987 and tried to improve this But again, while giving better prices to the factories, the subsidy element was unfortunately again introduced and that wrong notion of sugar being available at cheaper rates goes into the minds of the people. While sugar at my factory level is not available at Rs. 12|- or Rs. 13|- a kilogam, it is being sold at Rs. 8|- or Rs. 7.50 or Rs. 9|- Then a person is always under an impression that sugar is always cheap item.

But I am sorry to say that the hon. Opposition leaders have not, really tried to analyse this question which requires very serious consideration. Sugar cycle will come and will be coming. But unless we take effective steps to check it, we will face this problem again and again. There was a talk about 1979. I am only replying to the question which was raised. I was the Minister of Cooperation in the Government of Maharashtra and Mr. Vasantdada Patil was our Chief Minister. We were having a very personal relation with Morarji bhai. We came here to make a request to Morarji bhai. We told Morarji bhai. Control must be there.

हमने कहा कि डि-कंट्रोल मत कीजिए । अभी तो आपको दो-ढाई रुपए में शगर मिल जाएगी लेकिन 6 महीने बाद आपको 15 रुपए में भी नहीं मिलेगी ।

He did not listen. It came true. For four months, sugar was cheap. It was available at Rs. 3||-, Rs. 2.50 a kilogram. Sugar factories were compelled to do that. But, Mr. Vice-Chairman, after four months, it was not available even at Rs. 15|- a kilogram and the Government which was speaking about decontrol of sugar immediately came with a heavy hand for controled. Sugar again. The Government immediately controlled the situaton. It is a very complicated situation and it requires a very, very serious consideration.

Hon. Shri Jaipal Reddy has said one thing. We have been listening to this question for the last two days. Sir, I am a junior Member. All these people are very senior Membes and seasoned politicians. But they again and again say, 'Prime Minister, Commerce Minister, Finance Minister, this Minister and that Minister'. Don't they know that a file on any issue or a problem of a particular Ministry may go through half-a-dozen Ministries? These Ministries will be concerned with the issue. But this does not mean that because the file has gone to so many Ministries, all the Ministers must come before the House. Don't they understand this simple philosophy of joint responsibility? The Minister represents the Prime Minister and he enjoys his confidence. To whichever Ministry the file may have gone or the problem may ave been referred to, ultimately it is the Minister of that particular Ministry who is responsible, who has the duty and the authority to deal with the problem. I sometimes feel that even some of those seasoned politicians really don't behave like seasoned politicians. You try to find out some scandal. In the case of OGL, how can you say that there is a scandal in this? Mr. Pranab Mukherjee was very correct when he said, "Patil Saheb, don't ask me to give it to some people. I will make it open to every-body". That is why it is on OGL. In OGL, how could there be corruption? Now the ISGIEC has proved. We contracted two lakh tonnes of sugar, and we were able

to get 90,000 tonnes out of which we have already distributed about 25,000 tonnes in Delhi. We are having 500 shops in Delhi where we are selling it for Rs. 14.50 per kilogram. That is in retail. There is a possibility of some people bringing it cheaper. Somebody has asked: Why are there so many prices? I would like to tell the hon. Members that for every ship-load, there is different price. For every ship-load of sugar, we have to discuss with somebody. We may be bringing it from Brazil, we may be bringing it from Guatemala, we may be bringing it from Thailand. When we bring it from Thailand the price is one. When we bring it from Brazil, the price is different. So, there is going to be a difference. When it has been made absolutely open, how are you going to say *qaya kardiya*? The point is, sugar is less. It has to be brought. The Government made all the efforts. Mr. Kalp Nath Rai persistenly told us, and he was absolutely right when he said that unless we protect the interests of the farmers, it is not possible. What is the reason that people are going away from sugarcane to other crops? It is because sugarcane crop requires 18 months, while in other crops, he gets them in four months. Another thing is that unless he gets a better price, he switches over to other crops. Are you aware, Sir, that in Punjab, all the sugar factories are closed within just two months because all the sugarcane producers of Punjab have switched over to soyabin and sunflower? Unless we are able to give them a better price, a remunerative price, it is not possible. In Maharashtra the High Court gave a ruling that you must give Rs. 750 for every tonne. When every tonne of sugarcane will be paid Rs. 750 which produces only 90 kilo of sugar, you cannot expect sugar to be cheaper. I know the Government has made efforts. Mr. Kalp Government nas made efforts. Mr. Kalp Nath Rai has not been partial to the industry. He has been correct. He has been trying his best. And how could you blame him when until December, the production was two lakh tonnes more and we thought we could get at least ten lakh tonnes more in Uttar Pradesh? Somebody was asking. Who is responsible Our policy is responsible. We have to make a change. And Mr. Kalp Nath Rai did make a mention that you must tax khandsari. Without that, they would not come to even grounds. And it is true that Uttar Pradesh produced the largest cane. But it is also true that UP is number two in sugar production. It is Maharashtra which is number one in sugar production. And the reason is very simple. 90 per cent of cane in Maharashtra comes to sugar factories and only 35 per cent of it comes to the factories in Uttar Pradesh. You have to convince the people. You go to the sugar factories. And he will be convinced if he gets a better price, if he gets a better deal. Now, they are saying:

भ्रष्टाचार करते हैं, जैसे भगवान के पास जाते हैं कि चुनाव आ गया पानी बंद कर दो तो फसल के बारे में पैसा कमाएंगे ।..

What a statement? What kind of an argument? Has anybody got any authority or capacity to tell God, "you create drought in Maharashtra? I think, in the Opposition, there are respected leaders. They must also know that there are situations which require better understanding, better consideration and not apposition alone. They are saying that a scandal of 5,000 crores has taken place. Every time, the amount is increasing. On the first day, Joshiji said.

स्कडल हो गया, पहले हजार करोड़ बोलते थे, आज 4 हजार करोड़ बोलते हैं, कल 10 हजार करोड़ बोलेंगे

This is not a first. (*Interruptions*) Yes, the situation was difficult. The situation was different. It has to be dealt. with And I think, Mr. Kalp Nath Rai as the Food Minister tried his best to solve the problem. The Government tried to solve the problem. It is on the way of solution Already 6 lakh tonnes of sugar has been

contracted and 3 lakh tonnes of sugar has come. Sugar prices in the country have gone down by Rs. 50 per quintal. In another 15 days they will go down further, and I am quite sure that this Government, with its policy, will be able to supply sugar and bring our country out of this problem. There is no question of a scandal and no question of looting the consumers, but the question to be remembered is that the consumer, the farmer and the industry will have to be given justice, and then only the sugar industry will be able to perform its duty for the country. Thank you, Sir.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal. Hon. Vice-Chairman, Sir, this discussion has been going on for quite some time. It has been described as a muddle, scam and so on and so forth. But, even with the fear of having to differ from some of my friends of the Opposition, I would like to describe this as a collapse of the myths which the economic philosophy of of the new liberalization policy had built up. This is a blow to the theory that price stability can be achieved by market-driven forces. I will try to elaborate on this question. In fact, the crisis that we are witnessing today involves the adverse effects of liberalization in different sectors of the economy.

To start with, one of the issues which is being debated is, as the Government has put it and as some of the Congress Members were putting it, the unexpected shortfall in production. Now, I do not understand why they are saying that this was unexpected, because sugar is one item in which the amount of manufacture can be quite precisely estimated, particularly if we see the past, we will find that in India there has always been a three year cycle where peaks and tops have come. Therefore, with the manufacture picking up in 1991-92, it can be very well estimated that it will reach the top in the year 1993-94. Secondly, the figures were very much there with the Agriculture Ministry and the Government as a whole, that the crop area under sugarcane was coming down. Why was it coming down? Was the Government not offering proper prices to the sugarcane growers? This was not a fact. As opposed to other agricultural commodities, sugarcane growers were given more prices than the minimum that was announced by the Government. Still, sugarcane growers were opting for other agricultural products because the new mantra that the commercial viability of agricultural production, the question of producing for export, was driving the activities of the sugarcane growers and, therefore, we saw that even though more prices than the minimum were being offered, the area under sugarcane cultivation was coming down. The next point is that we know that there were drought conditions in Maharashtra. Now the whole blame for the fall in the production o fsugar is being thrust on the U. P. Government because of certain policies that the U. P. Government had implemented. It is being argued that even some of the sugarcane which was available, was diverted to production of gur and khandsari. It is the same principle of market-driven, profit-driven economic activity that led to certain diversions in such sectors.

So, we have seen the scandal developing. Even the Food Ministry in the third week of January was saying that we were going to produce 112 lakh tonnes. Already the Indian Sugar Mills Association itself had said, "Our production cannot be more than 100 lakh tonnes Some other estimates were showing even less. Then they came with a *suo motu* statement that only 96 lakh tonnes would be produced. Even with the wherewithal for making a proper estimate, the estimate which was done was upgraded with the inside knowledge that there would be a shortfall ultimately. Different players were brought into the field, into the economic arena, who looted, who fleeced the people of this country.

I say this because in November itself there was a note put up by the Food Secretary that we would have to import sugar. Consistent demands were made on

the Food and Civil Supplies Ministry that sugar would have to be imported, but the Food Ministry was saying that there was no need to import sugar from the international market. As late as March 9, the Cabinet Committee on Prices came to the conclusion that sugar would have to be imported. On the 15th of March a statement was made that under the OGL duty-free sugar would be imported. We see that by that time there was a huge spurt in the price of sugar in the international market, and subsequently also there was a huge spurt. I do not want to go into the details. Jaipal Reddyji and others have already pointed out the sequence, how one statement after another was being made by responsible quarters of the Government that we would have to import ten lakh tonnes of sugar, thereby contributing to the inflationary spiral in the price in the international market.

As a result of that, there are broad divergences on the actual loot of the Indian people. Joshiji was pointing out some figure, over dollar 400 per tonne. The minimum estimate is that least Rs. 5,000 crores.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please conclude now.

SHRI NILOTPAL BASU: Yes, just two minutes.

At least Rs. 5,000 crores has been fleeced from the people, and it has gone into certain appropriate places. Now the Minister has to come out concretely, and the Government will have to tell us about the actual money which has gone out like this from the country, from the pockets of the people and about who were responsible for this. Mr. Jaipal Reddy was making a point about the STC's delaying tactics.

I am also on a concidence that one of the biggest imports that was made was by one of the ex-chiefs of the STC, now the Vice-Chairman of the Great Eastern Shipping, one gentleman named, Sudhir Mulji, who imported about 2 lakh tonnes. In fact, after the issuance of the Open General Licence some imports were made. Suddenly we saw that imports had stopped because big players had come in to further shoot up the prices. Why did the market-driven approach of stabilising the price of sugar come in? Why were there no more imports under OGL? Why did STC have to step in? It was because this was a crisis, which had developed because of the inbuilt economic philosophy of the new policy of liberalisation.

Sir, the Food Minister and the Government owe an explanation. Certain concrete things have to be said. He said that he cancelled the order of the FCI because he was abiding by the recommendations of the PAC. Now, the point is that the PAC was saying that it passed strictures on the FCI because the FCI delayed imports and incurred heavy losses. They have repeated the same folly. Therefore, they are answerable to us.

I would like to conclude in a lighter vein. I do not want to be discriminatory against the Food Minister. There is at least one section of the people who will shower their congratulations on him. They are the sections of the diabetic patients, because our Food Minister has ensured that there will be no more provocation for them But for that he cannot escape the responsibility of giving us certain concrete information about what went wrong and the people are, who benefited from the entire crisis.

SHRI DINESHBHRAI TRIVEDI (Gujarat): May I seek a clarification? I understand the other House is going to adjourn perhaps *sine die* today. We do not have the two Bills for which this Session has been extended coming before us for discussion. What is going to be the business before us? Are we also going to adjourn *sine die* or not? If we know this we can plan our programme accordingly.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We do not have that communication here. We do not have to decide no it now. Appropriate decision will be taken. There is no problem. Now we continue with this business. As and when a decision is taken, we will let you know.

श्रीमती सुषमा स्वराज : न हमारे पास आर्डिनेंस है, न हमारे पास बिल है, इसलिए लगातार जीरो आवर चलेगा।

SHRI M M. JACOB: What is going on actually is not the issue.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: I am saying this because each and every minute costs tax payer's money. That is our concern.

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The issues raised by various hon. Members will be answered by my colleague, Kalp Nath Ji, who is incharge of the Ministry of Food. But two or three things I would like to place in proper perspective which the hon. Members will appreciate.

On this general issue which is affecting us if we work out a policy, it will help us in future. When I come to that point, the hon. Members will appreciate that on a number of occasions they have raised it on the floor of the House.

The first question raised was why the decision on OGL was taken apart from the fact that it was in conformity with the policy. Both Joshi Ji and Jaipal Reddy Ji have referred to it. Most respectfully I would like to submit that this is one of the recommendations of the PAC in the 45th Report submitted on 19th April, 1993. When they analysed the sugar import in the year 1989, one of the recommendations in paragraph 1.68 was that sugar should be imported under OGL. That report is available and it is the recommendation of the Public Accounts Committee. It was presided over by no less a person than Vajpayee Ji himself.

The second question arising out of that is this. When you place a commodity under OGL, naturally you would expect even the agencies owned by the States will apply their commercial judgements. State agencies in this new dispensation will have to operate in two sets of situations. One, when we give them a direction, that you have to do it, you have to import on Government account, they will do so.

4.00 pm.

But if you ask them to apply their own commercial judgement and take a decision from the commercial propriety point of view, then, you will have to leave it on their decision. Keeping that in view, I would like to clarify on the third point, I would like to clarify about the price of sugar. We were told that sugar was available at cheaper prices. Till today, right at this moment, sugar is under the OGL, duty free concession is available to everybody. So, if somebody has received the offer of sugar at cheaper prices, dollar 100, dollar 120, dollar 90, dollar 80, why are they not importing it? The STC less than what other people are buying, and MMTC don,t have any special advantage. The duty free concession for import is applicable to everybody, so, why are they not using that facility?

What has been the trend in prices? I have some figures. These figures are not secret figures or classified figures. The price of sugar on the 15th April in the daily market of London was dollar 325.50 per tonne.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: What was the price in September and October, 1993?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Dr. Joshi, I will come to it a little later. But there is the other side of the coin also. You will have to judge it. The question is that on the 15th April, 1994, the price of sugar was dollar 325.50 per tonne on the spot. You will have to add freight cost to it. The average price of sugar which STC and MMTC have bought after taking into shipment cost to be delivered in June to November was dollar 382 per tonne and dollar 380 per tonne respectively.

I would like to inform the House that even the MMTC in their judgement started buying from April itself. In April,

they entered into a contract for import of 78,000 tonnes of sugar which will be available. Therefore, these issues are to be kept in view. Instead of passing on the buck and trying to find out about corruption, they should see what has been done.

If you permit me, I may remind hon. Members and some of the Members were there in this House at that point of time, in 1980 also we had the shortage of sugar. At that time also I was the Commerce Minister. We had to import some sugar but not in large quantities. I think three or four lakh tonnes. Some allegations were levelled and some astronomical figures like Rs. 4000 crores, Rs. 5000 crores, Rs 10,000 crores as quoted now were quoted. There also ultimately it was found that the value of that net total quantum of the commodity imported was much less than the quantum of commission which was suggested to have been transacted. I simply put a question, is there any businessman in the country who will give Rs. 120 as commission to sell a product of Rs. 100? Therefore, let us not allow ourselves to indulge in these fancy figures and baseless allegations. The fact of the matter is that there has been a shortage. As the Food Minister informed the other House yesterday, we could detect sugarcane diversion earlier sometime in December and January.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Mr. Minister, will you yeild for a minute? May I know from the Minister whether it is a fact that Mr. Shivraj K. Patil, one of the gems in the sugar industry pointed out in the month of October to the Food Minister and even to the Commerce Minister that there was going to be a shortfall of 15 lakh tonnes of sugar. The Sugar Federation is the only institution in the sugar industry which supplies figures to the Government of India regarding shortfall of sugar production or excess of sugar production... (*Interruptions*)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I think I nave understood his point. The other Minister will reply to it. I am intervening on alimited question I am not replying to the debate. You can address all the questions to him.

The first point is, where was cheap sugar available? Mr. Shivaji quoted some parties. From the MMTC some offer came. Then they got the address. When it was contacted, it was found that tnere was a party in that name, but that company had been declared insolvent, it had been liqutdated and some cases were going on against it. Those who are aware of this fact know that particularly to take advantage by opening some letter of credit and get some concessions, they do it Particularly in Brazil, the monthly rate of interest is 48 per cent. When an item is exportable, the interest rate comes down from 48 to 16 per cent. There are some unscrupulous elements moving around. If tney can enter into some sort of contract. they will try to make money out of that. Therefore, I think the Public Accounts Committee took the right decision to indicate that our transactions should be only with *bona fide* parties who are registered, who do genuine business even in that case, if we have to pay some more.

Mr. Jaipal Reddy has said that information has been leaked. I think there is no need to leak. You may look at the type of questions we have to answer here every day If there is an edible oil shortage, the first question will be how much I am going to import. You can notice that every year. Look at the fluctuating palm oil prices in Malaysia when India enters into the market. There is no need to leak anything Trade will speculate. Parliament will debate. There, the figures. the quantum, come out and naturally, it will have its impact. I have no doubt that sugar prices increased substantially when after the 18th April, it was known to the world market that India was going to intervene. particularly the STC|MMTC, not OGL, You will notice

that during the period between 15th March, when Mr. Kalp Nath Rai announced the decision of importing sugar on OGL, and 18th April, the movement was slow. You look at the position from 18th April, after 20th April, when it was announced that STC|MMTC was going to intervene. We had to do it for a depression on the domestic market to give a warning to the speculators. It is a double edged sword. This is not a matter of scoring a debating point. This is an area where we shall have to work out a mechanism through which we can, perhaps, effectively intervene and ensure national interests, interests of the national industries consumers and all concerned. Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir... *(Interruptions)*.

SHRI BIPLAB DASGUPTA: One small point, Sir. *(Interruptions)*.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Will you kindly regulate, Sir?

SHRI BIPLAB DASGUPTA: Sir, this question can only be answered by the Commerce Minister. He is very close to the Prime Minister. Is it not true that the Prime Minister's Office repeatedly asked that the import should be made, arrangement should be made from March 9 and it was not until May 19, that the actual order was issued? That too after Mr. Kalp Nath Rai cancelled the global tender by order for importing. From March 9 to May 19, for almost two and a half months, no action had been taken by the STC, That is no. 1. The other point is, is it true that the Prime Minister himself had urged the Minister to balance he deficit by imports and even then no action was taken and whatever action was taken by the bureaucrats' was perhaps because of the understanding that the Prime Minister wanted it and because of the feeling that if it was delayed, the price of sugar might become uncontrollable? Maybe, the Commerce Minister would care to answer these question.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: If the hon. Member had listened to me carefully, he would have noticed that I have myself stated that the MMTC had imported 78,000 tonnes in April, itself from 6th April, to 26th April. The private parties also started importing sugar. I had the whole list of figures. They started importing sugar in March-April. So, the import was taking place. What is the cumulative amount? We were told that the STC and the MMTC had a total import of about 6,36 lakh tonnes and 6.26 lakh tonnes of sugar had been contracted by the private parties. This took place from the day of announcement of OGL. Some contractors entered earlier and some later.

SHRI S. JAIPAL REDDY. The hon. Commerce Minister, I must say, has clarified many matters but he has also admitted many matters because he has said now, "The international price began to rise only from the last week of April." So the STC and the MMTC had all the time in the world between January and April, between March and April. And he admitted that through OGL sufficient quantities could not be contracted. This inabiilty to contract sufficien quantities was known to the Government. Therefore, the question arises as to why the STC and the MMTC did not go in for contracting sufficient imports in March itself. Was it because the question of subsidy was no settled? Why did you allow time to be lost in settling the quesion of subsidy beween you and the Finance Minister?... *(Interruptions)*.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I think it is fair if he would be replying to the debate... *(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: It arises out of your intervention. It was, perhaps, on December 15 when the Cabinet Committee on Prices met, that a decision to import about 15 lakh tonnes of sugar was taken. The proposal was made. Your Ministry participated in that

[Dr. Murli Manohar Joshi]

meeting and MMTC and STC were asked to import sugar. When there was such a large gap of ten lakh tonnes, what was your Ministry doing? Wasn't it your responsibility to arrange for these imports right after December 15, when there were proposals, when there was a demand, when the Food Ministry was saying like this. What steps were taken by MMTC and STC to import? What arrangement was made between STC and MMTC? You your itself said it... *(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Would you please take your seat now?

This question will be answered by my colleague. He will give the figure. In November this year and also in November, 1993 the production of sugar was more than that in November, 1992. Therefore, the question of taking the decision to import in December does not arise at all. The decision was taken on 15th March and the action was taken thereafter.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the shortfall of sugar was actually noticed by the Government during the month of November, 1993 itself. Sir, in November, 1993 the Cabinet Committee on Prices had instructed the Food Ministry to import sugar for maintaining proper supply throughout the country. Sir, in December the Food Ministry submitted a statement regarding the production of sugar to the Cabinet Committee on Prices, but the statistics submitted by he Food Minister were rejected by the Cabinet Committtee on Prices. The argument put forth by the Food Minister to the CCP that they can augment the sugar supply within India, i.e. domestic production, was also rejected by the CCP. Then, Sir in February, 1994 the State Trading Corporation has initiated the negotiations but during the month of March, again, the CCP has given an instruction—this is not the first instruction, but the second instruction—to the Ministry of Food to see that sugar is imported immediately. Then only they woke up. Then, the Food Corporation of India entered the field. They negotiated. Once the negotiations were cancelled by the Ministry, the State Trading Corporation took the charge and started negotiating. Sir, what is really the question? The last Economic Survey has clearly stated that the cultivated area of sugarcane has actually come down fro m3.82 million hectares to 3.62 million hectares. The cultivated area of sugar-cane is going to be reduced further by 3 per cent. It was mentioned in the Economic Survey. It means that last year itself the Government was aware of this fact. The hon. Members from the Treasury Benches said that the sugar production was maintained at 240 million tonnes. The reason attributed for the price rise is diversion of production from one sector to another sector, that is, from sugar to khandsari and gur. It is not so. If it had purchased sugar in the month of November, 1993 instead of May, the Government could have saved more than Rs. 1,000 crores. I want to know from the hon. Minister how much quantity of sugar has been purchased by the private traders from October to November 15. Then we can find it out. The private traders are looting the money of the public. The sugar barons have issued a statement to the Press that they can supply the imported sugar at the cost fixed by the Government unit at the same time, they have stated that they would not part with the free-sale quota. I would like to know whether it is a fact or not. Subsequently, the Government has given another press information that the Government has negotiated with the sugar barons and they have agreed to supply the imported sugar. It is not so. A fortnight before this information was provided by the Government to the Press the sugar barons himselves had stated that they would not part with the free-sale quota. It means that they dominated the Government. How could

they do that? The ex-factory price of sugar in May, 1991 was Rs. 772 per quintal. Now, the ex-factory rate is Rs. 1,400 quintal. How has it happened? How has the Government accepted it? Why has the molasses been decontrolled? What I feel is that if the amount realised by the sugar factories by the sale of molasses is entirely credited into the sugar factories' accounts, the price of sugar would not have risen to Rs. 1,400 at all. There was a bungling between the Ministry and the sugar barons. That is my charge. Therefore, I want to know why the subsidy for the maintenance of buffer-stock of sugar has been reduced from Rs. 62 crores to Rs 25 crores in the Budget. This also gives the information on that. The budgetary provision on sugar is going to be cut down. That is another indication for the private traders. Why did the Government allow export of sugar to the tune of 191-thousand tonnes during the period April-September, 1993 when they came to understand that the country would face a shortage of the commodity? Sir, more than one lakh tonnes of sugar was stacked in several factories. The Government was not aware of that. The Government said that it was not aware of that. It ought to have been supplied to the Government godowns. But the sugar factories have not supplied. The Government doesn't demand from the factories that they should supply that one lakh tonnes earmarked for them. Had they supplied that, we would have saved Rs. 126 crores from imports. The Secretaries are fighting against each other. The PMO is fighting with the Food Ministry. The Food Ministry is fighting with the STC and the MMTC on the one hand and the Food Corporation of India on the other hand. When they are engaged in fighting over the issue, the truth is that we have lost more than Rs. 1,000 crores in terms of foreign exchange. The sugar barons have actually looted the public of more than Rs 1,000 crores. Not only the Food Ministry, not only the other Ministries, not only the PMO, but the entire Cabinet is responsible for this. (*Time bell rings*) Just one minute, Sir, This is one of the biggest scams after 1991. Therefore, I accuse that the entire Cabinet is responsible for this scam. A Joint Parliamentary Committee should be constituted to find out the real truth behind this scam and to find out the responsible persons. Accountability and responsibility is the basis of democracy. We should see to it that the people responsible for this type of scam are punished according to the law of the land.

SHRI V. NARAYANASAMY: Are you referring to the scam?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Why are you provoking? You please try to conclude.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: You people have allowed the sugar barons to loot the public money. (*Interruptions*)...You people have allowed them. You have talked about Delhi. The Government of India has reduced the prescribed sugar supply to Delhi by five per cent. That is why the shortage is more in Delhi. Are you punishing the people of Delhi because they did not vote for you?

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, a lot has been said about the details of the production of sugar, the factors which have led to he shortfall or the circumstances in which sugar has to be imported from other countries and the various means which were adopted for the import of sugar.

Sir, I am slightly on a different aspect. It is the spirit of the debate on the part of he Opposiion which is important. What has characterised the motivating force behind the personal allegations, personal abuses and reckless character assassinations not even excluding the hon. Prime Minister? It is this political phenomenon of character assassinations, personal political abuses and personal denigration which has charaterised the politics of the Opposition for the last

25 years. Ever since 1969 they found it impossible to fight the Congress and the top leaders of the Congress party.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): May I ask him to yield?

SHRI MADAN BHATIA: I am not yielding.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Sir, I am not a point of order.

SHRI MADAN BHATIA: Sir, I am on my legs. I am not yielding.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Sir, I am on a point of order.

SHRI MADAN BHATIA: Mr. Gujral, you were not here when these speeches were made.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Sir, I am on a point of order. He cannot stop me from raising a point of order.

Sir, the hon. Member has mentioned about the last 25 years. Does it include all those years when the Congress party was in the Opposition?

SHRI MADAN BHATIA: Don't worry, I will deal with that aspect. When I say the Opposition, it includes the opposition to the Congress which is the Opposition today. You should have the understanding and the intellect to appreciate what I am saying. It is no use standing up and making a point. Sir, what has happened to the politics of the Opposition? Ever since 1969, the whole politics in this country has been polluted by all these Opposition parties opposed to the Congress, whose only motivating force has been character assassination of the top leaders of the Congress and the Congress party. This is exactly what is happening today. They did their worst. They did their worst from 1977 to 1980 to destroy Mrs. Gandhi on the personal level. But, what happened to them? The Janata Party was simply wiped out from the surface of India. What has happened to the BJP? The BJP was accusing the Congress party and the leaders of the Congress party on a personal level. They demolished the Babri Masjid and by demolishing the Babri Masjid. .... (*Interruptions*).

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : आज 20 रुपए किलो शक्कर बाजार में बिक रही है, आपकी सरकार को कोई लेना-देना नहीं है और कांग्रेस पार्टी कितनी ईमानदार है यह तो दिख रहा है। 20 रुपए किलो जो सरकार शक्कर बिकवा रही है, उसको एक मिनट भी यहां रहने का अधिकार नहीं है ।

SHRI MADAN BHATIA: What happened to the Janata Dal? The Janata Dal was born of in political deceit, political betrayal, hypocrisy and falsehood. What has happened to the Janata Dal today? It is no longer a national party It has been reduced to a regional rump in a few provinces, in a few States of India.

This is the fate of the kind of politics ... (*Interruptions*)

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI (Orissa): Sir, on a point of order... (*Interruptions*).

SHRI MADAN BHATIA:...which has been played by these Opposition parties in the last 25 years... (*Interruptions*).

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: I want to raise a point of order... (*Interruptions*).

SHRI MADAN BHATIA: But the tragedy is... (*Interruptions*). They haven't learnt lessons from history and they are continuing to indulge in the kind of politics... (*Interruptions*)

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: The language that he is using against the Opposition parties is objectionable. Hypocrisy and so on are unparliamentary

and they cannot go on record... (*Interruptions*) Secondly, I would like to ask my friend whether the Congress (I) is a national party? It is not there in Uttar Pradesh. It is not there in Bihar. It is not there in Orissa...(*Interruptions*) It is not there in West Bengal. It is a small regional party... (*Interruptions*)

SHRI MADAN BHATIA: If the Congress (I) is not a national party... (*Interruptions*)...

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: It can be thrown out of the country... (*Interruptions*)...

SHRI AJIT P. K. JOGI: Mr. Vice-Chairman, Sir, he cannot even name the head of his party... (*Interruptions*). There are so many heads... (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Mr. Biju Patnaik was defeated in the Parliamentary election. Mr. Laloo Prasad Yadav was defeated... (*Interruptions*).

SHRI AJIT P. K. JOGI: Where is your party? Where is your head? (*Interruptions*). Mr. Bommai is temporarily heading a headless party...(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Bhatia, you have two to three minutes only. Please conclude.

SHRI MADAN BHATIA: If they don't interfere, I will finish in five minutes. Sir, this Government has made a constitutional history under the leadership of the hon. Prime Minister, Shri P. V. Narasimha Rao. Never before in the history of Parliamentary democracy was a minority Government able to achieve so much and do so much good to the country as this Government has done in three years under the leadership of Shri P. V. Narasimha Rao. And this is exactly the reason why Shri P. V. Narasimha Rao is again being picked up for personal attacks in the last one year...(*Interruptions*). They will have to meet the same fate as happened when their attacks were directed against Mrs. Gandhi, when Mrs. Gandhi emerged again as the one leader who completely wiped the Janata party from the surface of politics. It is up to the people... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please, Mr. Virumbi, don't disturb.

SHRI MADAN BHATIA: The people of India have come to realise... (*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: Has the speech any relevance to sugar at all? (*Interruptions*)

SHRI MADAN BHATIA: What is the image of Shri P. V. Narasimha Rao? (*Interruptions*) The image of Shri P. V. Narasimha Rao among the people of India is the image of a leader of wisdom, of sagacity, of equanimity ...(*Interruptions*)

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Are we discussing Shri Narasimha Rao here? This is a Short Duration Discussion on sugar and not on the Prime Minister...(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Bhatia, kindly conclude ...(*Interruptions*). Allow him to conclude.

SHRI MADAN BHATIA: They are afraid of the increasing political image of the hon. Prime Minister among the people of India. Therefore they started their political attacks. They started attacking the hon. Prime Minister on the issue of Agni and Prithvi, they miserably failed in this. Then they started attacking him on his proposed visit to the United States. That had also failed. Now, they started attacking the Prime Minister on the sugar issue.

...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Virumbi, please listen to him. Mr. Virumbi... (*Interruptions*)...

SHRI MADAN BHATIA: They demanded that the Prime Minister should come. Is there a question which cannot be answered by the Minister of Food? By simply making a demand that the Prime Minister should come, they are repeating it like parrots... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Bhatia, please conclude... (*Interruptions*)...Mr. Virumbi, Please sit down.

SHRI MADAN BHATIA: Mr. Vice-Chairman, I should be allowed to make my point clear. The total consumption of sugar from 1992 to 1993 was 124 lakh tonnes. In November, 1993, it was estimated by the Ministry of Food on the basis of the figures of the production of sugar cane given by the Ministry of Agriculture, that the total production was going to be in the range of 106 lakh tonnes. The Government at that time had a buffer-stock of 31 lakh tonnes of sugar. Therefore, the total sugar estimated by the Ministry of Food in November, 1993 which would be available from 1993 to 1994 was 137 lakh tonnes. The demand estimated was 124 lakh tonnes. No Minister of Food in his senses could possibly have recommended import of sugar in November, 1993. The allegation which is being made by some hon. Members in the Opposition that repeated proposals were made for import of sugar in November, 1993, is nothing but total travesty of truth. It is a total falsehood. There was no such proposal at all. On the country, it was estimated that the sugar in the country would be sufficient to meet the demand of the people from 1993 to 1994. It is only in January, 1994 when the Ministry of Food had seen a slight increase in the price of sugar that it swung into action and recommended to the Cabinet that import of sugar might become necessary.

Then what happened? It was the Sub-Committee on Prices of the Cabinet which took the decision in the middle of March that sugar should be brought under OGL. Then, sugar is put on OGL. The allegation which has been made that money was sought to be made by particular individuals and particular Ministers becomes totally false because every person, every citizen in this country is entitled to import sugar from anywhere in the world. If import of sugar is so permissible, if there is some shortage of sugar, I will ask the Opposition one simple question: Why did not the traders and the investors in this country rush into sugar business and import it immediately? They did not do this because at that particular time although there was some increase in the prices, the traders did not realise that the price would increase to such an extent that they would be able to make profits. Otherwise, the 'raders' would have rushed in and it would have been a gold mine. It is only when the price shot up to Rs. 14 and Rs. 14.50 that sugar started being imported by the private investors. There are 12 biggest sugar importers in this counry. And at what price have they imported? The same price at which the suga has been imported by MMTC and STC. And they still have the temerity to say that STC has imported sugar at an exorbitant price. You can make these allegations. On the basis of these allegations, you can castigate individuals. But that is the politics of personal abuse to which I have the drawn the attention of this hon. House.

The last point that I would like to say is this. This increase in price is not only because of shortage in production for which no Ministry is responsible. The shortage in production also arose from two facts. One is the policy of the Uttar Pradesh Government. Second fact is hoarding of sugar by the traders. I would like to ask the Opposition because some of the Opposition parties are in power in some States: Which State Government—whe-

ther the State Government of West Bengal whether the State Government of Uttar Pradesh, whether the State Government of Bihar—took any steps against the hoarding by traders? They did not. And an artificial shortage of supply was also created by the hoarders. (*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am on a point of order.

SHRI MADAN BHATIA: No action was, taken by the State Government against the hoarders.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please go to your seat. (*Interruptions*) Please conclude.

SHRI MADAN BHATIA: Instead of this, they were raising slogans against the Minister of Food. We have been listening to those slogans. But it brings nothing but shame that this hon. House has been used for the personal denigration of individuals and political leaders and political figures. They are also your colleagues. You should show some decency before making these allegations, and before shouting the slogans. After all, you can also be on this side. You should show some deceney... (*Interruptions*).

SHRI AJIT P. K. JOGI: They will never be on this side. Don't worry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You please conclude.

SHRI MADAN BHATIA: This is all that I have to say.

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the inherent sugar muddle is yet another incident which highlights the callous attitude of the functioning of the Union Government. This has also brought to focus the communication gap within the Council of Ministers. Sir, for the first time since Independence, the nation witnessed such a bizarre incident wherein the Food Minister, the Food Secretary, the FCI, the Cabient Secretariat, the Civil Supplies Minister and the Prime Minister's Office accused each other for landing the country on to this avoidable hardship.

Sir, one fails to understand as to what this Government has been doing after knowing well that the sugar production in the country has come down ofer the year. From 134.11 sakh tonnes during 1992-93 season, it decreased to 106.09 lakh tonnes, and it is expected to decrease further to 96 lakh tonnes. Since the Food Ministry already had these figures before it, it was incumbent on the part of the Government to have taken necessary measures like import of sugar to save at least the common man from undue hardship. Sir, the use of sugar is no more limited to urban areas and upper and middle classes. Every household is using sugar. And a large chunk of people depend on sugar given through the public distribution system. Since the bufferstock of sugar had run out, the common man could not get sugar through PDS. Since the Public Distribution System is maintained by the State Government, they have to bear the wrath of the people for no fault of theirs. Repeated requests from the Tamil Nadu Government to send the Central Pool allocation in advance to meet the requirement had fallen on deaf ears. Even the sugar allocation for the PDS in Tamil Nadu is based on the 1981 Census. The Government at the Centre is never realistic in its approach. Otherwise, it would not have kept silent for yeads together despite repeated appeals by our hon. Chief Minister for increased allocation on the basis of current population.

Now, that wisdom has dawned so late is no secret. The Government claims to have imoted sugar, and the Minister in his statement has said that the upward trend in the open market price of sugar has been arrested. The facts are, however, to the contrary.

Even in Delhi, under the very nose of the Government, sugar is sold at Rs. 18 a kg. The poor people, particularly in the rural areas, are unable to buy sugar. It is time the Government acted in a more responsible way.

Since the Government is responsible for the muddle, I want the Prime Minister to fix responsibility on persons who have failed in their duties and take necessary action to show to the country that this would not happen ever again.

Thank you, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I must compliment the hon. Member from the other side, Mr. Bhatia, for the nice speech that he has made, because the only conclusion from his speech is that the Governmen can fail but accountability cannot be established, persons can be at default but they cannot be named parties can fail but if criticism is made, it becomes too much political, too much partisan. This is the singular way in which the entire system of the country is sought to be eroded, because we are bidding goodbye to the question of accountability. Can it be denied that there has been a tremendous rise in the price of sugar, can it be denied that the sugar price increased because of scarcity, can it be denied that the increase in the price of sugar has resulted in hardship to the common people? If it is so, on whom should the accountability lie? Who is responsible?

Sir, I hold the Minister of Food singularly responsible for all that has happened. I do not blame the Government in its entirety because the Government as a whole is not to be held responsible. A section in the Government and some among the Ministers have always been saying that there has to be import of sugar. I do not name the entire bureaucracy because a section of the bureacracy has always been telling the truth, that the country should import sugar. That there is a scarcity of sugar was very much palpable in October 1993. Why? Because the area under sugarcane plantation was much less in 1993 than it was in 1992, and there was also the danger of diversion of sugarcane. Taken together, there was a signal for scarcity, and the Government, particularly the Ministry of Food, deliberately slept over the problem of scarcity in order to enable the sugar lobby to reap the benefit and make profit. That is the charge against the Government.

The question is being raised, how could we know that there was the need to import sugar? Sir, it was in October-November that Mr. Sen, the Secretary of Food, in a straigh'-forward note to the Minister, pleaded for the import of sugar, and the hon. Minister of Food did not allow the note to proceed to the Cabinet Committee on Prices. If I am wrong let there be an inquiry. Let there be a full-fledged inquiry where all the papers related to the sugar scandal may be asked to be produced. I am told that the Prime Minister has seized all the papers. If it is so, let there be an inquiry. This is point number one.

Secondly, after that there have been four meetings of the Cabinet Committee on Prices. In most of the meetings it is the Minister of Food who has opposed the idea of import of sugar. If I am wrong, let the minutes of the CPP meeting be placed before parliament of before any impartial enquiry body.

In November, 1993 there was a categorical propocal at least from two Ministers. Let me not name them so that they are not embarssed. They pleaded for import of sugar. The Cabinet Committee also pleaded for import of sugar in the CCP meeting in November, 1993. It was ignored. Why was it ignored? It was because Mr. Kalp Nath Rai stated that he wanted one month's time to see whether the production of sugar would increase. He held out a threat of resignation also. He is reported to have said at one point of time, "Sugar

can be imported only over my dead body."... (*Interruptions*).

Sir, I always plead for proper scrutiny of all the information that I have with me. If there is anything wrong, let there be an inquiry. I plead for an inquiry. Maybe, my information is not true. But, whether it is true or not, the Minister of food had always opposed the idea of import of sugar. It is because of that, despite some of his colleagues having a different idea, that no decision on import of sugar could be taken.

I would like to know whether Mr. Sen. Secretary of the Department of Food, had put a note to the Minister and whether that note was allowed to be sent to the CCP or it was prevented from being sent to the CCP. What was the reason?

Secondly, Sir, in November, 1993, at least two Ministers—one of them is the Minister of Civil Supplies—suggested that there should be import of sugar at least for the Public Distribution System. That was just not done. Who was responsible for it?

In the next meeting in December, 1993, there was again a proposal. That proposal was scuttled, and in that meeting . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You have already consumed double the time you were allotted.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am coming to the end.

In that meeting, the Minister of Food was instrumental in seeking reduction of the supply of sugar in the open market.

In he third meeting also a proposal was made. In the third meeting one Minister and one important officer said, "Before import of sugar is put in the OGL list, let us import sugar for the PDS." That suggestion was just turned down. Before sugar was sought to be imported for the Public Distribution System, it was put on the OGL system. As a result, the country lost and it lost heavily.

Not only that; also, when the Government decided to purchase sugar, is it true or not that suggestions were made to purchase sugar from the manufacturing countries and not form the sugar lobby? Is it true or not that an important Minister of the Government of India suggested, "A neighbouring country does have a surplus stock of 5 lakh tonnes of sugar, and that sugar can be made available to India on request at a reasonable price."? I want to know whether that request was turned down because a lobby was active, overactive to purchase sugar from the international lobby?

Therefore, Sir, there is an element of collusion. One part of the Government deliberately tried to scuttle any move for import of sugar. One part of the Government deliberately overstated the potentiality of the production of sugar. One part of the Government deliberately collided with the international sugar lobby. One part of the Government gives the handle to the domestic lobby to reap money out of the price increase arising out of the scarcity. Another part of the Government, they are few in number, had been pleading for import of sugar. Their pleading always has been turned down. It has been turned down because the Minister in charge of Food stood in the way. He is personally liable for not importing the sugar; he is liable for being instrumental in reducing the supply of sugar in the open market. he is liable in suggesting that the people of India should not purchase sugar at such a low price when the price of sugar in the international market is so high. He was very much critical because the common people were purchasing sugar at a low price. Therefore, he wanted

to increase the price of sugar at one point of time. Therefore, putting all these points together, I have no hesitation in saying that the hon. Minister and his importent aides, the principal characters in the bureaucracy, who have been aiding and abetting, should not be allowed to stay in office. If he does not resign, let him face an inquiry. Let the inquiry be headed by an impartial body. I do not mind if they are from the Congress Party. I know there are people in the Congress party who are equally agitated just like us. Therefore, let us not look at the problem from the narrow partisan angle. It is a scandal of scandals How long the country is going to see that money is going to be made by these people at the cost of the interest of the nation? money was made out of the Bofors: money was made out of the securities scandal and money is being made out of the sugar scandal. We want accountability to be established. We do not want people to go scot-free. In order to establish accountabiliy , it is time for the hon. Minister to leave his office and face an importial inquiry.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मानमीय उपसभाध्यक्ष जी, वर्तमान केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री के अन्तर्गत इस देश का जो संसदीय लोकतंत्र का ढांचा है यह बिलकुल नष्ट हो रहा है। हमारे संसदीय लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं। वर्तमान सरकार के अन्तर्गत एक मंत्री के सचिव का क्या रिश्ता होना चाहिए सचिव से, एक सचिव का दूसरे सचिव से क्या रिश्ता होना चाहिए या जो पी.एम.ओ. का का र्यालय है उनका दूसरे सचिवों से क्या रिश्ता होना चाहिए, सब बिकुल नष्ट हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, चीनी का उत्पादन घटने वाला है और यह घट रहा है, इसके संबंध में बराबर सरकार को जानकारी थी और इस चीज को खाद्य मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि 1991–92 में चीनी का उत्पादन 134 लाख 11 हजार टन था, 1992–93 में यह घट कर के 106 लाख 9 हजार टन हो गया और 1993–94 में 96 लाख टन उपादन होने की संभावना थी। लेकिन चीनी की कीमत बराबर बढ़ रही थी आज जैसे कि सभी को जानकारी है कि इस देश में चीनी 20–21 और 22 रुपये किलो मिल रही है और कहीं कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब एक प्रधानमंत्री जी का दौरा अमरीका के लिए तय नहीं हुआ और अमरीका जाते जाते उन्होंने केबिनेट सचिव को इस बात की हिदायत दी कि चीनी के सकट को दूर किया जाए, उसके पहले कोई कार्यवाही नहीं की गई। 17 मई को एक टेंडर फ्लोट करने का आदेश हुआ और उस समय यह आदेश हुआ जिस समय कल्पनाथ राय जी जैसे कि बताया गया गाजीपुर में चुनाव के दौरे पर थे। मैं जयपाल रेड्डी जी को यह बताना चाहता हूं कि कल्पनाथ राय जी उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में 85 सीटों में से 81 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई, केवल चार लोग जीते जिसमें कल्पनाथ जी थे भी हैं। लेकिन नकी अनुपस्थिति में, बगैर इनसे पूछे हुए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया गया लेकिन इनकी अनुपस्थिति में, बगैर इनसे पूछे हुए ग्लोबल टेंर जारी कर दिया गया। केवल डेढ़ दिन का समय दिया गया। 17 मई, 1994 को टेंडर फ्लोट किया गया जिसमें कहा गया कि 18 मई, 1994 के बारह बजे से 19 तारीख सुबह 9.30 तक फेक्स या टेलेक्स से टेंडर भेजे जा सकते हैं। इस तरह से ग्लोबल टेंडर के लए समय दया गया डेढ़ दन का, 36 घटे का। डेढ़ दिन का, 36 घटे का और खाद्य सचिव की ओर से इस बात का स्पष्टीकर दिया गया है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन खाद्य मंत्री चूंकि इस देश में लापता थे, इसीलिये खाद्य मंत्री के साथ सचिव का सम्पर्क नहीं हो पाया। आज के जमाने में टेलेक्स है, आज के जमाने में कलेक्टर अवेलेबल रहते हैं कमिश्नर अवेलेबल रहते हैं, टेलीफोन है, फैक्स हैं, लेकिन खाद्य सचिव का यह कहना कि खाद्य मंत्री से सम्पर्क नहीं किया जा सका, इस बारे में मामले को संदिग्ध करता है। दूसरी ओर मैं इस

ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक कामर्स सेक्रेटरी है, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इस केबिनेट सेक्रेटरी पर कि 24 मई, 1994 को जो सचिवों की बैठक हुई उसमें मिनट्स को मिस रिप्रेजेंट किया गया, यानी 24 मई, 1994 को कई सचिवों की बैठक होती है और उसकी जो कार्यवाही है, उसमें तोड़ मरोड़ करके उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया। यह आरोप सीधा-सीधा कामर्स सेक्रेटरी ने यहां के केबिनेट सेक्रेटरी पर लगाया है। तीसरा, जब खाद्य मत्री लौटकर आते हैं, 19 तारीख तक सुबह 11, साढ़े 11 बजे के करीब तो इसका एक इन्टरव्यू मैंने पढ़ा है "पायनियर" में 29 मई को कि ये अपने खाद्य सचिव को बुलाते हैं और टेण्डर कैन्सिल किया उसको आदेश देने के पहले खाद्य सचिव से कहते हैं।

"I called for the Food Secretary and asked him, "Can you write on the file that the Prime Minister asked the Cabinet Secretariat to import sugar?" He said he could give the answer after half-an-hour. He returned to say he could not and at 1.20 P.M. I cancelled the decision to import sugar."

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो खाद्य मंत्री और खाद्य सचिव के बीच में कामर्स सेक्रेटरी ने आरोप लगाया है, इसके सिलसिले में आखिर क्या सत्यता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आपको समाप्त करना पड़ेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं समाप्त तो कर रहा हूं।

दूसरे, 21 मई की रात को जब उन्होंने उस टेण्डर को कैन्सिल कर दिया इसके बाद भी जो एफ०सी०आई० है उसने ग्लोबल टेण्डर के सिलसिले में एक आर्डर किया और 21 मई की रात को 9 बजे तक खुले रहने का निर्देश दिया। मैं पूछन चाहता हूं कि यह सही है या गलत है और अगर ऐसा हुआ तो यह किसके निर्देश पर किया गया क्योंकि सबसे बड़ी जो एक्सट्रा कान्स्टीट्यूशनल अथारिटी आज देश में है वह पी०एम०ओ० है, प्रधान मंत्री का कार्यालय है। प्रधान मंत्री का कार्यालय हर मंत्री के कार्य में हस्तक्षेप करता है। प्रधान मंत्री का कार्यालय हर सचिव के कार्य में हस्तक्षेप करता है। पी०एम०ओ० को इस बात का अधिकार नहीं है। हमारा कन्सेप्ट है, ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी का और उस फार्म की गर्वनमेंट यहां पर है। हर मंत्री स्वतन्त्र है, फैसला लेने के लिये। लेकिन पग पग पर यहां पर प्रधान मंत्री का जो कार्यालय है वह एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल अथारिटी है और वह अपने अधिकारों का तथा जो उसके पास अधिकार नहीं है, उनका भी दुरुपयोग करता है।

इसलिये अन्त में मैं इन सारे तथ्यों को रखते हुए केवल एक बात की मांग करना चाहता हूं कि यह देश में एक बहुत बड़ा घोटाला है, यहां पर गरीब आदमी पिस रहा है, चीनी हमारे सार्वजनिक उत्सवों, शादी और अन्य प्रकार के जो उत्सव होते हैं, उसमें रहती है, हर व्यक्ति को चीनी की जरूरत पड़ती है और आज चीनी 20-22 रुपये प्रति किलो मिल रही है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिस तरीके से मूंदड़ा कांड के सिलसिले में कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत चीफ जस्टिस छागला से जांच करायी गयी थी, उसी तरीके से इस सारे मामले की जांच कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत करायी जाये.. **(व्यवधान)** ... वह राजस्थान सरकार ने करवायी है ... **(व्यवधान)**

अंत में मैं इस बात की मांग करता हूं कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत इस सारे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के एक सिटिंग जज से करायी जाए, तभी सारा मामला देश के सामने साफ होगा कि इसमें प्रधान मंत्री दोषी है, खाद्य मंत्री दोषी है, खाद्य सचिव दोषी है या कामर्स सेक्रेटरी दोषी है या प्रधान मंत्री का कार्यालय दोषी है।

श्री जनेश्वर मिश्र : (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, कल, जो हमारे बुजग

[श्री जनेश्वर मिश्र]

और भा०ज०पा० के मैम्बर हैं श्री विष्णु कान्त शास्त्री जी उन्होंने हमसे यहां आकर कहा कि तुम चीनी के सवाल पर भी नहीं बोलोंगे ? तो हम उनका भाव समझ गये। उनका भाव था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन करती है इसलिए हम पर आरोप था कि तुम लोग चुप रहते हो और उन्होंने कहा कि देश भर की जनता चीनी के मामले में तबाह है और तुम नहीं बोलोगे। तो उन के बोलने का मतलब था वे लोग जिस तरह के नारे लगा रहे थे—चीनी चोर गद्दी छोड़ो और पता नहीं क्या-क्या उस हल्ले गुल्ले में हम भी हिस्सा लेते, हमारी पार्टी भी हिस्सा लेती। 5 P.M. पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मुल्क की आम जनता के सवाल पर, चाहे वह हमारे समर्थक लोग रहे हों, चाहे विरोधी रहे हों, जब राजनीति में निर्णय समाजवादी पार्टी का आदमी लेगा तो वह किसी पक्षपात के चक्कर में नहीं फसने वाला। लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूं कि अपने लोगों से, अपने से मेरा मतलब विपक्ष के लोगों से है, कल जो गर्मी थी, और..... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : भा०ज० पा० को विपक्ष मानते हैं या नहीं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अपने लोगों को, भा०ज०पा० भी विपक्ष में बैठती हैं, उन सब लोगों से कि कल जो गर्मी थी कि कल्पनाथ राय जवाब देने के लिए उचित आदमी नहीं, इनसे स्पष्टीकरण हम लोग नहीं मांगेंगे, सीधे प्रधान मंत्री आएं, आज हमको स्पष्टीकरण देना है कि हम क्यों कल्पनाथ राय से स्पष्टीकरण के लिए और उस बहस का जवाब लेने के लिए मजबूर हो गए ? यह क्यों ? दूसरी तरफ सरकार से कहूंगा, कल्पनाथराय तो उस सरकार के छोटे मंत्री हैं, इनसे बड़ी सरकार है, जो नंबर एक पर लोग बैठा करते हैं उनसे, अगर बाजार में चीनी ठीक भाव पर मिलती रहती, गेहूं के मौसम में मैं कल्पनाथ राय जी का बयान पढ़ता था कि खाद्यान्न के मामले में हिन्दुस्तान स्वावलंबी हो गया, अब हम कहीं से नहीं मंगायेंगे। जब हमारे यहां गेहूं ठीक से पैदा होगा हालांकि सरकार गेहूं पैदा नहीं करती, सरकार गन्ना पैदा नहीं करती, चीनी पैदा नहीं करती, वह किसान करता है, मजदूर करता है, कारखाना करता है, लेकिन जब पैदावार ठीक होती है तब तो सरकार अपने पर सेहरा लेती है और जब पैदावार घट जाती हैं तो उसके बाद एक-दूसरे की तरफ सरकार झांकने लगती है। पहले जैसा कि मालवीय जी ने और कई मैंबरों ने बताया कि खाद्य मंत्री ने, माननीय मंत्री जी ने अपने सचिवालय के कई बड़े आफिसरों की तरफ ऊंगली उठाया है कि इन-इन सब का कसूर है। अपने मन से इन सब ने चीनी बाहर से मंगाने का फैसला कर लिया। हम से सलाह तक नहीं लिया अभी मैं सुन रहा था प्रणव मुखर्जी साहब को, इन्होंने कहा कि मार्च के महीने में और बयान भी कह रहा है कि मार्च के महीने में सदन को और संसद् को बता दिया गया था कि चीनी बाहर से मंगाई जाएगी, कमी पड़ रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि नवंबर अक्तूबर से, इनका सचिवालय कह रहा है कि अक्तूबर से चीनी की कमी पड़ने वाली है, खुद कल्पनाथ राय जी का वक्तव्य है जिसको हमने पढ़ा है, दो तीन साल पहले से जिस तरह से गन्ने का उत्पादन घट रहा है, चीनी का उत्पादन घट रहा है, इनको एहसास हो गया था कि अब चीनी कम हो जाएगी, बाहर से मंगाना है, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है, कुछ तो आरोप लगाया पहले अपने सचिवालय पर लगाया, फूड कार्पोरेशन पर लगाया। अब इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में यह जो गुड़-खांडसारी के किसान हैं इनको छूट दे दी गई। इनकी बक्री बढ़ गई इसलिए चीनी की पदावार कम हो गई। किसानों ने गन्ना कारखानों को कम दिया और महाराष्ट्र में गन्ना कम पैदा हुआ, यह इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। मैं इसको पढ़ रहा था और तब से मुलायम सिंह पर यह आरोप बनाने की कोशिश, उनकी सरकार पर यह आरोप बनाने की कोशिश कि गुड़-खांडसारी पर पाबंदी

नहीं लगाया, छूट दे दिया इसलिए चीनी का बाजार खराब हो गया। पहले इनका सचिव, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार से, फिर और किसी से हमने सुना कि बंगाल की सरकार से, फिर और किसी से हमने सुना कि राजस्थान की सरकार ये सारी विरोधी पार्टी की सरकारें हैं इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के बारे में नहीं कहा, क्योंकि वहां इनकी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे नहीं चलेगा। इसके बारे में अपनी दृष्टि साफ करनी पड़ेगी। एक संदेश चला गया इस सदन के मार्फत और सदन के मार्फत नहीं लगातार एक महीने से अखबार की मार्फत जिस तरह से मंत्रालय ने अपने आफिसरों को कभी पागल कह कर विभूषित किया है अखबारों में, कभी सनकी कह कर, कभी बेईमान कह कर विभूषित किया है, एक संदेश चला गया है कि हिन्दुस्तान का चीनी उद्योग उपभोक्ता के सिर पर एक मजा कर रहा है जिसमें अफसरशाह, नेताशाह और थैलीशाह इन तीनों की साजिश चल रही है। तीन लोगों के तिगड्ढे में आज चीनी का उपभोक्ता फंसा है। नेताशाह, अफसरशाह और थैलीशाह। अफसर को शक है, घंटी आपने बजा दिया हैं तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं... (**व्यवधान**) मेडन नहीं है, लेकिन हम अपनी बात कह देना चाहते थे। जल्दी-जल्दी में कहेंगे। अफसर को शक हैं मिनिस्टर पर कि अगर इससे पूछकर बाहर से चीनी मंगाएंगे तो यह मंगाने नहीं देगा। मिनिस्टर को शक है अफसर पर कि बाहर से जो चीनी मंगा रहा है, इसमें दलाली खाएगा। अपने मन से मंगा रहा है। हिंदुस्तान के जखीरेबाजों पर शिकायत हो रही है कि क्यों नहीं राज्य सरकारें इन जखीरेबाजों पर पाबंदी लगातीं।

उपसभाध्यक्ष, जो 20 रुपए किलो चीनी हो गयी, 22 रुपए किलो हो गयी और आप जानते हैं कि शादी के मौके पर यह चीनी की कमी हर गरीब आदमी को खलती है। तो उसका जवाब भी सरकार को ही देना पड़ेगा। हम विरोधी पार्टी के लोगों को नहीं देना है। हम तो आपकी आलोचना करेंगे, इसीलिए हम विरोध में हैं और आलोचना भी सिर्फ इस तरह से नहीं करेंगे बल्कि सरकारी पार्टी के लोग और हमारे मित्र जब चुनाव लड़ने जाते हैं, कल्पनाथ राय जी, अभी गाजीपुर के इंचार्ज थे मालवीय जी, अभी-अभी यह चुनाव हुआ है और उस गाजीपुर में इनकी पार्टी को 3 हजार वोट मिले है। यह उसके इंचार्ज भी थे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : 2 हजार।

श्री माखन लाल फोतेदार : साढ़े 3 हजार।

श्री जनेश्वर मिश्र : अब साढ़े तीन, दो और ढाई में कोई फर्क नहीं हुआ। इसका कोई मायने नहीं हुआ, लेकिन इनको सोचना पड़ेगा कि देश को जनता जो चीनी खाती है, उसका जो दर्द है वह रंग लाता है। आपका वोट इसलिए नहीं घट गया है कि मुलायम सिंह जी की सरकार बन गयी है और आप उसकी मदद कर रहे है बल्कि इसलिए भी कि जो दिल्ली से आप नीति चलाते हैं, उससे खाने-पीने की चीजों पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। हो सकता है कि इस सदन में विपक्ष की गर्मी ठंडी हो गयी हो। आज नारेबाजी नहीं हुई। फिर कल्पनाथ राय जी यहां बहस का जवाब देते और वह गर्मी ठंडी हो जाय, लेकिन आदमी का जो दर्द होता है, वह धीरे-धीरे पकते-पकते, चार साल, छः साल के बाद बगावत के रूप में उभरता है, जन-आक्रोश के रूप में उमड़ता है और एक मुद्दा बन जाता है। उपसभाध्यक्ष जी, जो लोग भी सरकार चलाते है, वह यह मानकर चलाते हैं कि वह चुनाव फिर जीत लेंगे। उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन वह पैसा-वैसा बहुत काम नहीं करता। उसके कोई बहुत मायने नहीं होते।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि एक महीने के अंदर, जबसे यह चीनी बाहर से आने लगी है, तब से चीनी के भाव में गिरावट आई है। मैं उसको ध्यान से पढ़ रहा

था कि कितनी गिरावट आई है। उसमें जो रेंज इन्होंने दिखायी है, उसके अनुसार "एस" ग्रेड की चीनी का थोक मूल्य मई, 1994 की स्थिति के अनुसार वह 1483 से 1630 रुपए प्रति क्विंटल के रेट में चल रही थी, वह घटकर 1994 की स्थिति के अनुसार 1463 से 1565 रुपए के रेंज में आ गयी यानी एक क्विंटल पर 20 रुपया, 15 रुपया घटा है। यह एक किलो पर 4 आने, 8 आने पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं। उपसभाध्यक्ष जी, एक तरफ तो जब यह सत्ता में आए थे तब चीनी 6 रुपए किलो बिक रही थी और आज बिक रही है 22 रुपए किलो। यह हमको गणित पढ़ा रहे हैं कि 8 आने और 4 आने के हिसाब से चीनी घट रही है। हमें कल्पनाथ राय जी या नरसिंह राव जी यही आश्वासन देते कि जब वह कुर्सी पर बैठे थ, उस समय के भाव पर चीनी का भाव कर देंगे तो भी समझ में आता। अब खांडसारी पैदा करने वाले गरीब किसानों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। उस समय हम लोगों की सरकार नहीं थी। पंत जी की सरकार थी और रफी अहमद किदवई उस समय खाद्य मंत्री थे। उत्तर प्रदेश में चीनी और गन्ने की कीमत तय करने के लिए उनकी एक कमेटी बनी। उस कमेटी में उन्होंने बताया कि जितने आने मन गन्ना बिके, उतने रुपए मन चीनी बिकनी चाहिए यानी गन्ना से चीनी तक 16 गुने का फासला होना चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी, उन दिनों नया पैसा, यह सौ पैसे वाला नहीं चलता था। वह रफी अहमद किदवई हम लोगों के नेता नहीं थे। वह कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अगर गन्ना पैदा करने वाला किसान यह मानता है कि, वह जो चीनी कारखानेदार को देता है तो उसका पेट नहीं भरता और जो सिंचाई के रेट बढ़े हैं, खाद के दाम बढ़े हैं तो वह अपने घर में अगर गुड़ पैदा करता है, तो क्या गुनाह करता है? उसकी तरफ उंगली उठाने की आज क्या जरूरत पड़ गयी?

उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिर में इन्होंने स्वीकार भी किया है कि चीनी की कमी को दूर करने के लिए गुड़ जैसी मीठी चीजों को बाजार में उपलब्ध कराने की कोशिश भी की जा रही है। इन्होंने यह अपने बयान में कहा है। आप एक तरफ गुड़ को स्वीकार भी करते हैं कि चीनी की कमी को दूर करने के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ायी जाएगी और दूसरी तरफ गुड़ पैदा करने वालों को यह दोष देते हैं कि इन्होंने खांडसारी और गुड़ ज्यादा पैदा कर दिया। उसका बाजार में आवागमन बढ़ गया, इसलिए चीनी का उत्पादन कम हो गया। तो हम यह मानकर चलते हैं कि इस समय जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनकी सोच किसान विरोधी है। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, लांछन लगा है और उस लांछन और आरोप को देखते हुए... (**व्यवधान**) ...

श्री शिवाजीराव गिरिधर पाटिल : एक मिनट। हमने यह कभी नहीं कहा है कि गुड़ बंद हो। यह तो ट्रेडिशनल है और वह फंडामेंटल राइट है किसान का। खांडसारी के बारे में कहते हैं क्योंकि खांडसारी वाले जब गन्ना ज्यादा होता है तो कौड़ी की कीमत में गन्ना लेते हैं और जब कम होता है तो ज्यादा कीमत में लेते हैं। तो आप खांडसारी की बात बोलिए। हमने गुड़ की बात नहीं कही है।

श्री जनेश्वर मिश्र : इसमें गुड़ भी लिखा हुआ है। इस वक्तव्य को आप पढ़ लीजिएगा, गुड़ और खांडसारी दोनों है। केवल खांडसारी नहीं है, लेकिन यह सच है कि गन्ना खरीदने वाला किसान जब गुड़ पैदा करने लगता है, खांडसारी पैदा करने लगता है तो चीनी पैदा करने वाले कारखानेदार की आंख में वह खटकने लगता है। एक चीनी की लाबी होती है इस देश में, जो गुड़ को पसंद नहीं करती, खांडसारी को पसंद नहीं करती।

उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने अगर मुझे टोक दिया तो अच्छा ही किया। यह दो लाबी लड़ती रहती है। एक किसान लाबी होती है और एक कारखानेदार की लाबी होती है। तो विपक्ष ने जो मांग की है, इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि देश की जनता जो चीनी खा रही है, वह बहुत कड़वाहट से खा रही है। उसके दिल में दर्द हो रहा है कि यह जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जिसमें हम लोग भी हिस्सेदार हैं, यह मत मानकर चलिएगा कि हम लोग हिस्सेदार नहीं माने जाते, उनका ध्यान नहीं रखते। हम सब के सब दोषी होंगे अगर कोई जांच करके जनता के सामने दस्तावेज नहीं गया कि सरकार, संसद और देश को चलाने वाले लोग निष्पक्ष थे, किन्तु कई मजदूरियों के कारण चीनी के दाम बढ़ गए। अगर यह संदेश देश की जनता के सामने एक दस्तावेज के रूप में, कमेटी की रिपोर्ट की शक्ल में नहीं गया तो हम लोग बहुत बड़े दोषी होंगे और उस दोष का खामियाजा आज नहीं बल्कि दो साल बाद, पाच साल बाद हमको भुगतना पड़ेगा।

आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): Mr. Vice-Chairman, so much of heat, passion and anger were generated over sugar. I hope I will be able to import sanity and rationality within the few minutes that I have at my disposal. My first question to the Minister is: Does he feel honourably that he is still Minister? (*Interruptions*). I am putting a question to you. I repeat: Do you feel honourably that you are still a Minister? You can answer that question. Sir, yesterday during his intervention in the Lok Sabha he is reported to have thrown up his hands and said and I quote:

> "What can I, as a Minister, do when in a democracy officials take decisions involving Rs. 400 crores?"

It is a candid admission of his helplessness. It is a candid admission that he is in conflict with his own officials. (*Interruptions*). It is a candid admission that even at this stage he is against import. I would like him to answer this question: Is it a fact that in Novemper last year his Food Secretary had put up a letter to him to be put up to the Cabinet, Cabinet Committee on Prices, that there was a serious shortage of sugar in the country and that import was necessary? Is it not a fact that he not only did not forwarrd that letter to the Cabinet Commitee on Prices, but he also had that letter changed into asking for more assistance for the prodution of sugar within this country at this late stage? I would like him to say, 'Yes' or 'No'. Even in the month of December he reported to the Cabinet Committee on Prices. These are his words. I quote:

> "As per the latest estimate, the production of sugar was expected to be around 107 lakh tonnes in the year 1993-94."

He made noises that the production would go up even to 115 lakh tonnes. That was his report to the Cabinet Committee on Prices. You look at his statement which he made yesterday where he said that the sugar production came down from 134 lakh tonnes in 1991-92 to 106 lakh tonnes in 1992-93 and now it has come down to 96 lakh tonnes. It this not a misstatement? Is this not an attempt to cover-up? Does it not prove that it is an attempt to create a false sense of complacency for which you are responsible because you have a lobby of vested interests, i.e. your friends, the sugar mill owners. There are so many names. I would like to know from the hon. Minister whether the Prime Minister has taken action to clip his wings. This paper says that the PMO has set up three Committees. The first Committee is set up under the Chairmanship of the Commerce Secretary, Shri Tejinder Khanna. It is expected to take all decisions concerning

[Shri G. G. Swell]

the import of sugar, not you, Mr. Minister. The second Committee that has been set up is to ensure adequate availability of sugar under the PDS. It has been set op under the Chairmanship of another person. The third Committee is set up to coordinate activities concerning macro management of sugar crisis, the overall management, not the management relating to one or two sugar mill owners who are your friends. Is it not clipping of your wings? What else have you got to do? Short of dropping you from the Cabinet, the Minister has taken away all your powers.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He is the most powerful man. He is the most powerful man by having the most powerful lobby. How can he be powerless?

SHRI G. G. SWELL: Now, I would like to know, Sir, whether there is any sense of self-respect in the Minister. How can he remain in office? (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is the most scarce commodity in the country

SHRI S. JAIPAL REDDY: That is to be imported through OGL...(*Interruption*).

SHRI N. E. BALRAM: And the Finance Minister will help us... (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS GUPTA: For that, you must put a question to hon. Manmohan Singhji whether he is ready to put this on the list of OGL...(*Interruptions*)...

SHRI G. G. SWELL: Since you have rung the bell...(*Interruptions*)

SHRI SATISH AGARWAL: He can only assure a duty free import...(*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I can assure you that it is definitely available in many of the Western countries for which the hon. Finance Minister is having the greatest regard. You can have it in abundance.

SHRI G. G. SWELL: Sir, since you have rung the bell, I would like to conclude in two or three or four seconds. I am not one of those who blame the entire Government for all that has happened. But somebody has to be held responsible. Who is to be held responsible? When there are precedents in the country, when even the Minister was not directly involved, yet because something wrong had taken place within his Ministry... (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is the market condition which is to be blamed and not the Minister.

SHRI G. G. SWELL: I am talking of the precedents...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Allow him to conclude.

SHRI G. G. SWELL: When something wrong had happened in the Ministry and although the Minister was not directly involved in it, yet the Minister had taken moral responsibility and had resigned. We have here the instance of the Finance Minister—there may be controversies about that—when he did offer his resignation. Now, here I am saying: not only myself, the entire House and also the Prime Minister are pointing their fingers at you. I would like to know whether you honourably feel that you are still the Minister. Please consider, Sir, if he still continues to be the Minister, what is he going to do to repair the damage? How much the people of India have had to pay in terms of this increase, abnormal increase, in the price o fsugar? How many crores of rupees the people of India paid as a result of your delay and your bungling. (*Interruptions*) I am not Coming to the Commerce Minister and the Finance Minister requesting for subsidy and all that. It was because of your bungling and because of all these kinds of publicity, the international sugar lobby

has raised the price of sugar from 250 dollars per tonne to over 400 dollars per tonne. The country needs an answer for all these things. Who is responsible? It is you who are responsible. How are you going to repair the damage? That is all. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Jagmohan. Your name was given but the entire time has been consumed by the Member of the U.P.G.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Sir, I had to raise a number of points but they have already been raised. The only point which has not been mentioned out of the list which I have is about public servants and I have to speak on behalf of them. What has happened in this case is that the public servants have been publicly rebuked and they have no defence. Apart from the personal affront to the officer concerned, my worry is that this will further deteriorate the morale of the services, their effectiveness and their efficiency. I think that this is a very important aspect today. Quite a lot of Indian problems are due to inefficiency, ineffectiveness lack of confidence in the officers and the rift that is there within the administration. I think this type of a thing that is happening is not good for the country. Also, while making public statements, we should display a greater maturity because this has a very great impact on the public servants. The second point that I would like to emphasise is that this type of problem can be inquired into by a commission of inquiry only or by a committee which has the power to interrogate, question, cross-examine, see the files and then come to the conclusion. You cannot just come to conclusions on the basis of reports as to how far the officials were responsible, how rar the other people were was responsible. In this connection. I remind you of one tthing. When the LIC scandal took place, it was only an item. But Pandit Nehru had no hesitation in ordering an enquiry. Mr. T. T. Krishnamachari owned the responsibility and he resigned. It was later decided that he was not the person who took the final decision in the matter. Since you have given me only one minute, I would like to confine myself to these threee points.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

(उपसभापति महोदया, पीठासीन हुईं)

श्री राज नाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदया, भारत सरकार के खाद्य मंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आज इस सम्मानित सदन में चर्चा हो रही है। हमारे विद्वान सदस्यों ने बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन बिंदुओं की चर्चा करके उनको पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन यह बात सच है कि इस कांग्रेस सरकार के रहते कई घोटाले प्रकाश में आए हैं। संसद के दोनों सदनों में उन पर गंभीर चर्चाएं भी हुई हैं और कई आयोग भी जांच के लिए बैठे, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटीज़ बैठीं लेकिन जांच के द्वारा कुछ भी निकलकर बाहर नहीं आया और किसी के ऊपर भी उन घोटालों की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। उसका परिणाम यह हुआ कि आज की राजनीति और आज के राजनीतिज्ञों पर से जनसामान्य का विश्वास उठता जा रहा है। आज सारे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि देश में चीनी की कीमतें इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं घोटाला है चाहे वह सरकार के किसी प्रतिनिधि के द्वारा हो अथवा ब्यूरोक्रेसी के द्वारा हो लेकिन कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है जिसके कारण चीनी की कीमत इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है। आज इस विषय पर हम सब बैठकर गंभीरतापूर्वक चर्चा कर रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं कि देश की जनता को यह विश्वास होगा कि भले ही संसद में चर्चा हो जाए, भले ही कोई कमीशन इंक्वायरी के लिए बैठा दिया जाए लेकिन इन बढ़ती हुई कीमतों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसे कदापि सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। न तो किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और न तो उसको दंडित किया जाएगा।

महोदया, मैं उन बिंदुओं की ओर अपने को नहीं ले जाना चाहता हूं जिनकी ओर हमारे विद्वान सदस्यों ने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि सारी वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसके पीछे मूल कारण यह होता है कि मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है। अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत से कहीं पर हमारी रंचमात्र भी असहमति नहीं हो सकती। अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत सही है कि यदि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो स्वाभाविक है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ेंगी लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमारा यह देश किसानों का देश है। यहां 75 फीसदी जनता खेती पर निर्भर करती है और बहुत बड़ी जनता यह मानकर चलती है कि गन्ने की खेती इस प्रकार की खेती है कि जिसके द्वारा हम अच्छी कीमत, लाभकारी कीमत हासिल कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में गन्ना किसानों को जैसा लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है ।

अब कुछ आंकड़े खाद्य मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में दिए हैं कि 1991–92 में यहां पर 134 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता था जो 1992–93 में 106 लाख टन हो गया और फिर 1993–94 में घटकर कुछ और हो गया। यह लगातार घटता जा रहा है, उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकारा है और इसके दो कारण उन्होंने बताए हैं। एक कारण तो यह बताया है कि गुड़ और खांडसारी के जो निर्माता हैं, उन निर्माताओं की ओर गन्ना किसान अपने गन्ने को डाईवर्ट कर देता है, उनको बेच देता है। इसलिए चीनी मिलों की तरफ गन्ना नहीं पहुंच पाता है। यह एक बड़ा कारण है, यह एक मूल कारण है जिसकी वजह से चीनी का उत्पादन गिर रहा है । चीनी का उत्पादन गिर रहा है। लेकिन हमें यह भी गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि चीनी का उत्पादन क्यों गिर रहा है। वह है गन्ना, गुड़ और खांडसारी के निर्माताओं की तरफ डाइवर्ट हो जाने के कारण। इसका कारण क्या है श इसका कारण यह है कि चीनी मिलें उन को लाभकारी मूल्य नहीं दे पाती है। इसलिए किसानों को जहां भी अपना लाभकारी मूल्य मिलता है वे वहां पर अपने गन्ने को ले जाकर बेचते हैं। इसलिए लाभकारी मूल्य न मिलने का सिलसिला एक लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन हम जब चीनी की नीति का निर्धारण करते है तो चीनी निर्माताओं के हितों का ध्यान रखकर करते हैं, गन्ने के उत्पादन करने वाले किसानों और उपभोक्ताओं का हम ध्यान नहीं रखते हैं। केवल शूगर लॉबी को ध्यान में रख कर अपनी नीतियां बनाने का काम करते हैं क्योंकि इसी शुगर लॉबी के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए चंदा मिलता है, इसी शूगर लॉबी के द्वारा अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए चंदा मिलता है। इसलिए हम उपभोक्ताओं और किसानों की उपेक्षा करते हैं। अगर मांग के अनुरूप हम गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो दाम बढ़ेंगे। लेकिन आप ने लाइसेंस प्रणाली में चीनी उद्योग को बांध रखा है। मुझे स्मरण है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी की सरकार थी तो उस समय 50 चीनी मिलों को लाइसेंस देने के लिए हमने अनुरोध किया था भारत सरकार से लेकिन एक भी चीनी मिल को लाइसस नहीं दिया गया। तो कैसे हम चीनी का उत्पादन बढ़ाएंगे, कैसे चीनी का दाम इस देश में कम करेंगे । यदि जान बूझकर इस चीनी के संकट को हम बनाए रखना चाहते है, यह सरकार चीनी के संकट को बनाए रखकर चाहती हैं, कि हम को चीनी विदेशों से इंपोर्ट करने का अवसर मिले तो जब चीनी का आयात करने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से उस में कमीशन खाने का भी अवसर मिलेगा । इस लिए जानबूझकर ऐसे नीति आप बनाते है, यह केवल किताबी नीति है, किताबी कमी है चीनी की। हमारा यह कहना

है कि चीनी उद्योग की लाइसेंस से मुक्त कर दें तभी जाकर चीनी संकट से आप इस देश को उबार सकते हैं।

महोदय हमारी सरकार ने डिकंट्रोल कर दिया मोलेसेज को, शीरे को। उस का परिणाम यह हुआ कि शीरे की कीमतें 5 से 6 गुनी अधिक बढ़ गई और आज स्थिति यह है कि उस की कीमतें 15 से 20 गुना बढ़, गई हैं। उसका लाभ किस को मिला? इसका लाभ मिला चीनी के मिल मालिकों को। जो शराब बनाते हैं, शीरे की कीमतें बढ़ जाने से उन्होंने शीरे से शराब का निर्माण करना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने गुड़ का उपयोग शुरू कर दिया। स्वाभाविक है कि जहां चीनी की कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं तो उस समय सामान्य लोग जो गुड़ और खांडसारी का प्रयोग करते थे, जो गरीब लोग गुड़ और खाडसारी से अपना मुंह मीठा किया करते थे, इन के दाम बढ़ जाने के कारण शुभ अवसरों पर भी जिस मीठे का उपयोग उन को करना चाहिए, वह नहीं कर पा रहे हैं। एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसमें गलती किसकी है? फूड सेक्रेटरी की है, कामर्स सेक्रेटरी की है, पी.एम.ओ., प्राइम मिनिस्टर आफिस के किसी प्रतिनिधि की गलती है, जब कोई आयोग बैठा कर सारे मामले की जांच कराई जाए तब तो यह बात निकल सकती है कि वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन मैं श्री कल्पनाथ राय जी को अच्छी तरह से जानता हूं। छात्र जीवन में यह हमारे नेता रहे हैं और बड़े दिलेर किस्म के नेता रहे हैं। लेकिन शासन की कुर्सी पर बैठने के बाद भी उन की दिलेरी और सदाशयता में अंतर नहीं आया है। आज मैं जब यहां बोल रहा हूं तो कल्पनाथ राय जी जब इस चर्चा के उत्तर देने के लिए खड़े हों तो निश्चित रुप से उसी दिलेरी के साथ यह बात कह सकेंगे कि आज इस देश में चीनी की जो कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं, उस के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं जिस दिन कल्पनाथ राय जी अपनी इस दिलेरी का परिचय दे देंगे वास्तव में वह देश के हीरो बन जायगे। आज इसी दिलेरी से वह मंत्री बने हुए हैं कल उनकी जगह कोई दूसरा मंत्री बन सकता है।...

उपसभापति : कल तो इनको चोर कह रहे थे। (**व्यवधान**) अभी आप छोड़ दीजिए आपका समय खत्म हो गया।

श्री राज नाथ सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि फूड मिनिस्टरी ने इस स्केयरसिटी के बारे में तथा चीनी को इम्पोर्ट किये जाने के बारे में प्रस्ताव केबिनेट के पास कब भेजा था, किस तिथि को भेजा था? दूसरे केबिनेट के समक्ष वह कब प्रस्तुत किया गया? इस बीच जो विलम्ब हुआ उस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए केबिनेट सेक्रेटरी जिम्मेदार है? मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर भी मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो देने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त और ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः विनम्रतापूर्वक चिर-परिचित होने के नाते खाद्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जरा मेरी तरफ नजर उठाकर देखें। मैं जानता हूं कि खाद्य मंत्री जी की नजर मुझ से मिल जायेगी तो पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें कि क्या प्रधान मंत्री कार्यालय के कारण सारा विलम्ब हुआ है? क्या प्रधान मंत्री कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार है; उन सारी स्थितियों से सदन को अवगत करायें जिनके कारण उन पर दोषारोपण हो रहा है। मैं चाहूंगा इन सब बातों से अवगत कराकर उन दोषों से मुक्ति प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपसभापति : कल्पनाथ राय जी उत्तर दीजिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं एक मिनट लेना चाहता हूं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: मैडम,...

उपसभापति : आपको क्या कहना है?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं एक मिनट लूंगा (**व्यवधान**) मेरी जानकारी में है कि प्रधान मंत्री ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप बीच में मत बोलिए। (**व्यवधान**)

Please sit down... (Interruptions) No, it is not going on record. I have first identified him. Yes, Mr. Ambedkar, what do you want to say?

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Madam, my name was listed for the discussion but I find that my name is being omitted.

SHRI G. G. SWELL: Give him five minutes, Madam.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Madam, I am not going to speak now, but quite often I find that whenever I give my name, this is what is happening. I do not know what is going on.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are no clarifications today. There was a meeting of the leaders of the various political parties and groups, and they said that there would be no clarifications and it would be in the form of a Short Duration Discussion. When we converted it into a Short Duration Discussion, every party or group had its allocated time. According to that, whichever group you belong to, we have not omitted anybody's name. We have kept everybody's name in order.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I do not know from which party which people have not spoken. There are many parties over here for which time has been allotted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You belong to the U.P. Group.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Madam, I know that I belong to a group. I would like to know who have been dropped from all other parties also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Two people spoke from your group.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: No, only one.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jagmohan, you spoke. Are you with the sme group or separate? Mr. Jagmohan also spoke.

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : माननीय उपसभापति महोदया, सभी मित्रों ने जो सवाल उठाये हैं, मैंने उन सब मित्रों की बातों को सुना है। यहां शुगर की कन्ट्रोवर्सी कब उठी ? तीन महीने पार्लियामेंट चला फरवरी, मार्च और अप्रैल, लेकिन महोदया इन तीन महीनों के अंदर इस सदन में या उस सदन में किसी भी माननीय सदस्य ने चीनी के संकट के सवाल को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, कामरोको प्रस्ताव के माध्यम से या किसी माध्यम से नहीं उठाया। ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उठाया, विजय जी ने उठाया। ... (**व्यवधान**) ...

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह बिल्कुल गलत है। मैंने तीन बार यहां यह सवाल उठाया, पिछले सेशन में और तीनों बार कहा गया कि... (**व्यवधान**).

Don't make a wrong statement. .... (*Interrnptions*) ...

SHRI MD. SALIM: The Special Mentions were there.

श्री कल्पनाथ राय : प्रधानमंत्री ... (**व्यवधान**) ... मैंने ... (**व्यवधान**). जब मैंने यह कहा है तो ... (**व्यवधान**) सुनिये, कोई मंत्री किसी प्रश्न का जवाब दे या कोई मंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे या कामरोको प्रस्ताव का जवाब दे, ऐसा कोई भी अगर दोनों सदनों में कभी आया हो तो मैं यह बात...

उपसभापति : स्पेशल मेंशन आया है।

श्री कल्पनाथ राय : स्पेशल मेंशन के लिये हम कोई जवाब नहीं देते ह ...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद सलीम : मंत्री जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। स्पेशल मेंशन के लिये यू आर एकाउन्टेबल। ...(**व्यवधान**)...

†شری محمد سلیم : منتری جی بالکل غلط بول رہے ہیں۔ اسپیشل مینشن کے لئے "یو۔ آر اکاؤنٹیبل" ... "مداخلت"۔

श्री कल्पनाथ राय : आप मेरी बात सुनिये।

उपसभापति : आप बैठ जाइये।

श्री कल्पनाथ राय : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो सवाल जवाब आमने-सामने होते हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आया। अगर स्पेशल जवाब आता है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: So what? That is the reason for this failure. Is this an argument?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Gupta, let him finish the reply.

श्री कल्पनाथ राय : मैंने आपकी बातें सुनी। हमारे साथियों ने जितने आरोप-प्रत्यारोप लगाये, मैंने उन सब बातों को सुना तो हमें भी अपनी बात को कहने का अधिकार होना चाहिये। मैं आदरणीय सिकन्दर बख्त साहब, जयपाल रेड्डी जी और जोशी जी से निवदन करता हूं कि आप बतायें कि कब पूरे देश के पैमाने पर यह संघर्ष या यह चीनी का सवाल पैदा हुआ? मैंने कहा कि अगर सवाल की कोई गंभीरता होती तो लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर उसी रूप में इसे लाया गया होता। लेकिन यह सवाल उठा 19 मई को।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सदन में पहले उठ चुका है यह सवाल। ...(**व्यवधान**)...

†[]Transliteration in Arabic script.

उपसभापति : एक मिनट। कल्पनाथ राय जी आप जरा एक मिनट बैठिये। अगर उनको यह पता नहीं है कि आपने स्पेशल मेंशन किया था तो मैं उनको यह बता देती हूं– क्योंकि कालिंग अटेंशन नहीं हुआ है, अगर कालिंग अटेंशन होता तो मंत्री जी यहां आते या कोई क्वेश्चन होता तो उसका जवाब उनको देना पड़ता। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट। मैं बता रही हूं। अगर स्टार क्वेश्चन होता तो उनको याद रहता। ...(**व्यवधान**)...एक आदमी बोलिये। ...(**व्यवधान**)...बहरहाल शुगर फैक्टरीज के क्वश्चन के बारे में उनको बता दें। कल्पनाथ जी यहां स्पेशल मेंशन के जरिये यह सवाल उठा था। हो सकता है कि आपके पास पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, आपने जवाब दिया हो या न दिया हो, बहरहाल यह हाउस में उठा था। ...(**व्यवधान**)...

श्री कल्पनाथ राय : आप मेरी बात सुनिये। आप...

श्री सिकन्दर बख्त : सिफ एक सवाल।

شری سکندر بخت : ختم تو کروائیے

श्री कल्पनाथ राय : आप नेता है, मेरी बात सुनिये।

श्री सिकन्दर बख्त : एक गुजारिश मेरी सुनिये। सदर साहिबा, पहली बात तो यह है कि स्पेशल मेंशन उठा हो, कभी भी उठा हो पर उठा है। दूसरी बात यह है कि यह सवाल उठा या नहीं उठा लेकिन चीनी की कीमत क्यों बढ़ी?

شری سکندر بخت : ایک گذارش میری سنئے۔ صدر صاحبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیشل مینشن اٹھا ہو۔ کبھی بھی اٹھا ہو میرے اٹھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال اٹھا یا نہیں اٹھا لیکن چینی کی قیمت کیوں بڑھیں۔

श्री कल्पनाथ राय : जोशी जी, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। आपकी बातें मैंने सुनी हैं। एक बार भी मैंने टोका-टोकी नहीं की है। आप मेरी बात सुनिये। कोई हमारी बात हो, आप हमें कहें कि सुधारिये तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी बात आप सुनिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सवाल पूरे देश के पैमाने पर उठा यह तब उठा जब 19 मई को मैंने एक कंट्रेक्ट को, टेंडर को कैंसिल किया। आदरणीय मल्होत्रा जी और इस सदन में सभी दलों के लोग मौजूद हैं, सिकन्दर बख्त जी, आप भी यहां केबीनेट मिनिस्टर रहे हैं, हम लोग विरोधी दल में रहे हैं। जनतंत्र में कभी आप सत्ता में आएंगे और कभी हम सत्ता में आएंगे। यह लोकशाही का तरीका है **(व्यवधान)** मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल कब उठा। एक मिनिस्टर जो लगातार तीन महीने तक संसद के अधिवेशन में मौजूद रहा है, क्या एक मिनिस्टर से संबंधित विभाग के मंत्री से राय लिये बिना, पूछे बिना क्या कोई बड़ा टेंडर या आयात-निर्यात का निर्णय देश के कुछ नौकरशाह ले सकते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नहीं ले सकते हैं **(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : नहीं ले सकते हैं **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, this is not the point. we are not interested to know that.

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA: I am interested in listening to Kalp Nath Rai.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He is beating about the bush.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): नौकरशाह भी प्रजातंत्र के हिस्से हैं। वह भी प्रजातंत्र को चलाने में मदद करते हैं। यह कहना बिलकुल गलत है कि वह कोई अपने अधिकारों के कारण या उनके सीमित होने के कारण, वह फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर मंत्री उपलब्ध नहीं है या फैसला करने में मदद नहीं देते हैं तो नौकरशाह नेशनल इंट्रेस्ट में फैसला कर सकते हैं और निणय ले सकते हैं **(व्यवधान)** मंत्री, अगर ऐसा है तो प्रधान मंत्री से कहें और उन नौकरशाहों को.. **(व्यवधान)** अपमानित करना या गाली-गलौज करना **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी: क्या भाजपा के आफिस का यह नियम है कि सिविल सर्वेंट इतना महत्वपूर्ण आखरी फैसला कर सकता है? **(व्यवधान)** क्या आपकी पार्टी का यह विषु है? **(व्यवधान)**

श्री आर. के. धवन (आंध्र प्रदेश): चतुर्वेदी जी, आप भी कई मिनिस्टरीज में इतने बड़े अफसर रहे हैं **(व्यवधान)** मिनिस्टर के बिना कोई फैसला नहीं कर सकता **(व्यवधान)**

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: कर सकते हैं अगर नेशनल इंट्रेस्ट में हो तो बिल्कुल कर सकते हैं **(व्यवधान)**

श्री आर. के. धवन: बिलकुल नहीं कर सकते हैं **(व्यवधान)**

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: फाइनेंस मिनिस्टरी से बात करने के बाद अवश्य कर सकते हैं **(व्यवधान)**

श्री आर. के. धवन: अपने आप ऐसा नहीं कर सकते हैं **(व्यवधान)**

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: लेकिन उसका इलाज गाली-गलोच नहीं है **(व्यवधान)**

श्री आर. के. धवन: चतुर्वेदी जी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिये **(व्यवधान)** क्या आपने कभी ऐसा फैसला अपने आप लिया था **(व्यवधान)** क्या बात करते हैं आप **(व्यवधान)**

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मैंने क्या फैसला लिया था, वह आप भी जानते हैं (**व्यवधान**) लेकिन मैं सब इस वक्त नहीं कहना चाहता हूं (**व्यवधान**)

श्री आर० के० पवन : चतुर्वेदी जी, सुनिये, मैंने आपकी वर्किंग देखी है (**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, this is not the issue of the House. I appeal to both of them... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing the discussion to go in this direction. (*Interruptions*). Please sit down. I am not allowing anything. Please sit down. I want to guide. Mathur Sahib, please sit down. I am not alllowing it.((*Interruptions*). Order in the House. (*Interruptions*) I will have to take some action. I am sorry, Mr. Mathur. If you are not going to abide by the thrust of the discussion.

श्री आर. के. धवन : हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है (**व्यवधान**)

उपसभापति: आप बैठिये प्लीज।

Just now the matter which we are discussing in this House is about the sugar crisis. We are not discussing who can take a decision, and who cannot take a decision. That is a separate matter, and that can be taken up at a different forum but not here. You may confine yourself to what we are discussing.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am on a point of order. Madam, my point of order is this. The hon. Minister in all seriousness had raised a question as to whether the Food Secretary could float a global tender without the knowledge of the Minister. He wanted us to give the answer. We may not be aware of the answer. We may be divided in our answer. But the Minister feels that it was wrong. He was not only speaking for himself but he was also speaking for the entire Government. If that is the position of the entire Government, how is it that the Food Secretary still remains at the same job? One of the two, either the Minister or the Secretary, should go. How are they co-existing? This is my point of order ... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not want any disturbance.

taries remain, the Government goes on

श्री कल्पनाथ राय आदरणीय उपसभापति महोदया, यह पब्लिक एकाउंटस कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें सभी दलों के—राज्य सभा के लोक सभा के भी सदस्य हैं... (**व्यवधान**)

SHRI S. JAIPAL REDDY: What is your ruling on my point of order?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It was pointed to the Minister not to me. In my Secretariat, there is no crisis of this nature.

श्री कल्पनाथ राय : आप लोगों ने जो सवाल उठाये हैं उन के दो पहलू हैं। एक वह पहलू है जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, दूसरा पहलू चीनी के संकट से हे दोनों पहलुओं पर मैं जवाब दे रहा हूं। यह पब्लिक एकाउंटस कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें सभी दलों के सबसे इंपारटेंट मेम्बर हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पब्लिक एकाउंटस कमेटी एक मिनी पार्लियामेंट है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। 1989 में जो शुगर स्कैंडल हुआ था उसके संबंध में जो उस समय के प्रधान मंत्री वी. पी. सिंह ने इसकी सी. बी.आई. इन्क्वायरी करायी थी और इसके बाद जो पब्लिक एकाउटस कमेटी ने रिपोर्ट दी तो इस रिपोर्ट में तीन बातें है आदरणीय रेड्डी जी, पहली यह है कि फूड मिनिस्ट्री जिसमें फूड कारपोरेशन शामिल था, वह इंपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात शामिल है कि कोई अनरजिस्टर्ड कम्पनी इंपोर्ट नहीं करेगी तीसरी बात यह थो कि यह जिम्मेदारी फिक्स की जाये कि कौन लोग जिम्मेदार है इस बगलिंग के लिये। चौथी बात, आदरणीय वाजपेयी जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि—

"The Committee would also emphasise that the mettar should be thoroughly examined bv the Minis-

try of Food with a view to devise the detailed remedial steps required to be taken in the matter of any future import undertaken by the Ministry so as to ensure that such imports are made in the most cost-effective and timely manner. The Committee would like to know the detained strategy proposed to be implemented by the Ministry in future in this regard."

यह रिपोर्ट 19 अप्रैल, 1993 को आदरणीय वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में सबमिट की । उसके बाद, आदरणीय चतुर्वेदी जी, हमारे फूड मंत्रालय ने 19 प्वाइंट की एक डिटेल्ड स्ट्रेटली जी भेजी– पब्लिक एकाउंटस कमेटी जो नयी बनी है उसको – क्या भेजी–

"Now since the STC is familiar all the technicalities of sugar imports, our imports should be made only through the STC.'

यह 14 फरवरी, 1994 . . (व्यवधान) मुझे आप बोलने दें । चतुर्वेजी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो रिपोर्ट 19 अप्रैल को सबमिट हुई उस आधार पर जो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी हमारे खाद्य मंत्रालय ने भेजी पब्लिक एकाउंटस कमेटी को उसमें क्या लिखा –

"STC should be asked to maintain a list of registered sugar dealers in the international market on the basis of their track record and financial standing. STC should address all enquiries only to such dealers."

इसके बाद क्या लिखा :

"If import of sugar is made through STC, the Food Corporation of India would require to arrange movement of sugar from ports to consuming destinations and distribution in the country."

ये तीन बातें 14 फ़रवरी, 1994 को की गई हैं । पब्लिक एकाउटस कमेटी, आदरणीय विरोधी दल के नेता, देश के सम्मानित नेता, की जो रिपोर्ट हुई जिसमें सभी दलों के लोग थे और उसके बाद स्ट्रटजी सभी दलों के लोग थे उसकी हमने डिटेल हमारे एफ़्वल से 14 फरवरी, 1994 को जब यह सबमिट किया गया पब्लिक एकाउंटस कमेटी को तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस रेकमेंडेशन के खिलाफ कैसे आचरण हो सकता था ? इसके खिलाफ आचरण कैसे हो सकता था? आदरणीय चदुर्वेदी जी, हमारे भूतपूर्व हो सेक्रेटरी (व्यवधान)

श्री त्रलोकी नाथ चतुर्वेदी : पी०ए० सी० मैं कंसिडर करूंगा. . . . (व्यवधान.

श्री कल्पनाथ राय : कंसिडर करेंगे और दूसरी बात यहां ओ०जी०एल० का सवाल उठाया गया (व्यवधान) यहां हमारे साथियों ने ओ०जी०एल० के सवाल पप मामला उठाया कि ओ०जी०एल० से क्यों चीनी मंगाई जा रही हें । तो श्री वाजपेयी और पब्लिक एकाउंटस कमेटी में क्या लिखा है :

"The Committee feel that if the import had been made through OGL, it would definitely have been both cheaper and quicker. The Committee feel that the better course at that time would have been to permit import through OGL only."

मैं कहना चाहता हूं कि जो यह निर्णय, इसके निर्णय का भारत की संसद में इसकी महान सर्वोच्च सत्ता के एक मंत्री से बड़े आप लोग हैं, मैर्क्स आफ पार्लियामेंट है । यदि इसकी बातों को सर्वसम्मत निर्णय को हम इंप्लीमेंट न करें तो आप क्या कहेंगे । दूसरे आइये शगर के मामले में. . . (व्यवधान) हमारे मित्रों ने. . . . (व्यवधान) दूसरी बात जब आदरणीय जयपाल रेड्डी जी जब फूड कारपोरेशन आफ इंडिया जिसकोहमने खुद लिखा है कि केवल डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग का काम करेगा जब उस एजेंसी का, जब बिना मंत्री से पूछे, पब्लिक ए,काउटस कमेटी के निर्णय के खिलाफ अगर कोई भी बड़े से बड़ा नौकरशाह निर्णय लेगा तो उस निर्णय को मैं रद्द करूंगा, लोकशाही का प्रतिनिधि होने के नाते ।

हमारे आदरणीय श्री जयपाल रेड्डी जी ने बहत सी बातें उठाई । अब शूगर की बात पर आइये । इतने लोगों ने बहस किया शूगर क्राइसिस, शुगर क्राइसिस मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदरणीय

नरसिंह राव जी की सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान में 1947 के बाद गन्ना किसानों का 12 रुपये क्विंटल दाम बढ़ाया, इतना दाम किस सरकार ने बढ़ाया और कब बढ़ाया, किसी समय बढ़ाया? (व्यवधान) मेरी बात सुनिये, एक आदमी ने किसानों की बात नहीं की ? जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उन किसानों के संबंध में, अभी हमारे मित्र ने कहा कि नम्बर में,हमारे सी०पी०आई० के मित्र ने, शूगर प्रोडक्शन इन 1992 28 लाख 25 हजार टन, शगर प्रोडक्शन दिस ईयर 1993 आन दिस.. **(व्यवधान)** देखिये, मुझे बात कहने दीजिये (**व्यवधान**) और सुगर प्रोडक्शन 1993 में 1992से ज्यादा हुआ, 29 लाख 71 हजार टन । यह सुगर प्रोडक्शन इकानोमिक सर्वे आँफ इडिया का है । अब जोशी जी, आप बतायें, अगर कृषि मत्रालय कहता है कि इस साल हमारा सुगर ोडक्शन यह होगा और उस सुगर प्रोडक्शन के आधार पर कितनी चीनी पैदा होगी... **(व्यवधान)**...

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Under which rule are you asking?

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I do not know the rule.

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभापति जी, जब कृषि मंत्रालय ने हमको रिपोर्ट भेजी कि पिछले साल से इस साल गन्ने का उत्पादन ज्यादा हुआ । पिछले साल 106 लाख टन हुआ और इस साल चीनी का उत्पादन 107 लाख टन होगा । तो पिछले साल से इस साल चीनी का उत्पादन ज्यादा होगा और हमारा 31 लाख टन कैरी-ओवर स्टॉक आलरेडी था जोकि हमारे बफर स्टॉक में था ।....**(व्यवधान)** मेरी बात सुनिये । मैं जानता हू कि आप लोगों को गन्ने के किसानों से कोई मतलब नहीं है और न आपको देश से मतलब है, इसलिये लगातार जनाज हिन्दुस्तान का उठता जा रहा है । मैं इस सबध में कुछ नहीं कहना चाहता । आदरणीय जयपाल रेड्डी जी, नवम्बर पिछले साल से इस साल नवम्बर में सुगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ । दिसम्बर में सुगर का प्रोडक्शन पिछले साल से ज्यादा हुआ । जनवरी में क्या प्राब्लम हुई कि जनवरी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुड़ मूवमेंट का वैन उठा दिया । हमने आदरणीय मुख्य मत्री जी को पत्र लिखा कि वैन मत उठाइये क्योंकि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है । वहां चीनी का उत्पादन आधा हो गया है और उत्तर प्रदेश में भी गुड़ मूवमेंट को नहीं रोका गया तो चीनी का उत्पादन कम होगा । उन्होंने कहा कि हमारी कैबिनेट ने फैसला किया है कि जब गुड़ के किसानों को 70 रुपये, 80 रूपये क्विंटल गन्ने का दाम मिल रहा है तो आप क्यों यह काम करेंगे लिहाजा मैं अपनी कैबिनेट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता । तब हमने 24 जनवरी को कैबिनेट सचिवालय को यह लिखा कि उत्तर प्रदेश में चूंकि मूवमेंट का वैन उठ गया है, इसलिये 10 लाख टन चीनी की शार्टेज होगी और इसकी व्यवस्था की जाये । एज ए खाद्य मत्री जो हमारी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को हमने पूरा किया और 9 मार्च को....**(व्यवधान)**... मेरी बात सुनिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : कैबिनेट सचिवालय ने क्या किया?

श्री कल्पनाथ राय : मेरी बात सुनिये । आप विद्वान हैं, केबिनेट मिनिस्टर रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आपने कहा कि कैबिनेट सचिवालय को चिटेठी लिखी । तो कैबिनेट सचिवालय ने क्या किया ?

श्री कल्प नाथ राय : कैबिनेट सचिवालय ने 9 मार्च को मीटिंग की । इस 9 मार्च की मीटिंग में फैसला हुआ । उपसभापति महोदया दो तरह की चीनी

है । एक फ्री-सेल की चीनी है और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यशन की चीनी है जोकि 9 रुपये 5 पैसे के हिसाब से पूरे हिन्दुस्तान के गरीब वर्ग को कन्याकुमारी से काश्मीर तक हम दे रहे हैं। यह शरू से दे रहे हैं । हमारी डयूटी है और हम कोटा अलॉट करते हैं प्रदेश सरकारों को । दिल्ली के लिये पहले हम जितना कोटा अलाट करते थे, उतना इस साल अलॉट कर दिया अब यह आदरणीय मदनलाल जी खुराना का काम है कि उसको 9 रुपये किलो के हिसाब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिकवायें । यह जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय शेखावत जी का है कि जो चीनी केन्द्र ने पी०पी०एम० के लिये अलाट की है, वह चीनी 9 30 रुपये 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिकती है । दूसरी चीनी, जो खाते-पीते धनाड्य लोगों की है जो कि फ्री-सेल मार्केट में बिकती है । मैं आपसे यह कहना चाहता हू कि इस चीनी में वह मार्केट फोर्स न लगे, उसके लिये ओ०जी०एल० में चीनी के लिये हमने 15 मार्च को पार्लियामेंट में घोषणा की । आप लोगों ने सवाल पूछे । उसमें 6 लाख टन चीनी के लिए ऑलरेडी प्रायवेट पार्टीज के कांटेक्ट किया है । दो-तीन लाख चीनी आ चुकी है ।

श्री कल्पनाथ राय : यह ठीक नहीं है । आप बीच में बोलते हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him onswer. (*Interruptions*)... Let him answer. (*Interruptions*)... Please let him answer. Don't disturb him. (*Interruptions*)...

श्री कल्पनाथ राय : मैं आदरणीय विरोधी दल के राष्ट्रीय नेताओं से अपील करता हू कि हमारा पाइट गलत हो सकता है, लेकिन आपकी बातें हमने सुनी हैं, हमारी बात आप सुनिये । आज 9/- रुपये किलो के हिसाब से चीनी पूरे हिन्दुस्तान के हर प्रांत को केन्द्रीय सरकार एलाट करती है, पूरा एलॉटमेंट होता है । ज्योति बाबू की भी सरकार को वही एलाटमेंट मिल रहा है, जो एलाट मेंट पिछले साल मिलता था ।

डा० दिप्लब दासगुप्ता : पूरा नहीं मिलता । ...(**व्यवधान**)...

श्री कल्पनाथ राय : देखो, इस तरह से बात करने से क्या होगा? कहां से बैरिस्टरी पढ़े हैं आप ? ...(**व्यवधान**)..मैं आपसे यह कहना चहता हू कि पी.डीएम. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी 9/- रुपये किलो के भाव से 3,35,000 टन पूरे हिन्दुस्तान के लिये रिलीज होती है । यह पूरे देश के लिये, तमिलनाड से लेकर जम्मू कश्मीर तक की गरीब जनता के लिये चीनी रिलीज होती है, आज भी हो रही है और 30 अक्तूबर तक इसका सीजन खत्म होगा तब तक रिलीज होती रहेगी । दूसरी चीनी, फ्री सेल की बाजार में जो बिकती है, जिसका सप्लाई और डिमांड के आधार पर दाम तय होता है, उसके लिये ओ,जी.एल. खोला गया है, कस्टम डयूटी को आदरणीय वित्त मत्री जी ने माफ किया है यानी जो चाहे हिन्दुस्तान का, वह विदेश से चीनी ला सकता है । छह लाख टन चीनी उन्होंने खरीदी, करीब ढाई लाख टन फिलहाल आ चुकी है और इसे दिल्ली में पब्लिक उपभोक्ता भडार में साढ़े 14 रुपये किलो बेचा जा रहा है । इसके 500 सेंटर खोले हैं । हिन्दुस्तान टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि इन 500 जगहों पर दिल्ली में साढ़े 14 रुपये किलो के हिसाब से जो चाहे चीनी खरीदे और इन उपभोक्ता भडार से खरीदे ।

श्री गुरुदास दासगुप्त : यह 14/- रुपये बहुत कमती दाम है ? ...(**व्यवधान**)..

श्री कल्पनाथ राय : मेरी बात सुनिये । मैं आपसे कहना चाहता हू...(**व्यवधान**).. आदरणीय जोशी जी, बी.आई०सी०पी० जो इडस्ट्रियल कोस्ट प्राइस ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट है कि चीनी की कोस्ट आफ प्रोडक्शन साढ़े 11 रुपये पर किलो है, जो चीनी सरकार लेती है वह 40 फीसदी तो 9/- रुपये किलो के हिसाब से लेती है । तो 9/- रुपये से साढ़े 11 रुपये यानी ढाई रूपये इस साढ़े 11 रुपये में जोड़ दें तो वह 14/- रूपये के भाव से चीनी मिल के गैट पर मिलती है और जो रिटेल में लाकर साढ़े 14

रुपये या 15 रुपये या 16, 17 रुपये में बिकती है ।

उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो बी.आई.सी.पी. की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तो गन्ने का दाम तय होता है, लेकिन बी.आई.सी.पी. की रिपोर्ट के आधार पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का दाम तय होता है । आदरणीय रेड्डी जी, आप हमें बतायें कि आज हमने हिन्दुस्तान के किसानों के गन्ने के दाम सबसे ज्यादा नहीं बढ़ाये हैं 1947 के बाद ? आदरणीय सिकन्दर बख्त जी, आपकी भी जनता सरकार थी, आप रहे हैं सरकार में, उस समय क्या नारा था ? कि—बोलो बेटा चरण सिंह की जय, गन्ना बिके पौने छह । (व्यवधान) . . .

उस समय लाखों एकड़ में खड़ा गन्ना जलाया गया या नहीं ? गन्ने के खेत ... दिये गये या नहीं ? आप आदरणीय मोरार जी की केन्द्रीय कैबिनेट के, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे है, मैं आपसे पूछता हूं । वर्ष 1977 से 1980 तक आपको हुकूमत चलाने का मौका मिला, उस समय किसानों का गन्ना पौने छह रुपये क्विंटल पर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था और आज किसानों को गन्ने का दाम 60/- रुपये क्विंटल कांग्रेस की सरकार दे रही है । (व्यवधान) . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कितनी महगाई बढ़ी है तब से ? . . . (व्यवधान) . . .

श्री कल्पनाथ राय : और, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं । . . . (व्यवधान) . . .

श्री सिकन्दर बख्त : चीनी के दाम का बताइये, उसमें क्या है? (व्यवधान) . . . चीनी तो 2/- रुपये किलो बिकती थी । (व्यवधान) . . .

श्री कल्पनाथ राय : मैंने बताया कि ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कोस्ट . . (व्यवधान) . . मेरी बात तो सुनिये । बी.आई.सी.पी. की रिपोर्ट के आधार पर, रिकमंडेशन पर चीनी का दाम तय होता है ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, what is this? He is defending the price rise. It is very unfortunate. (*Interruptions*).

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: The Minister is talking*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. Let him speak.

अभी बोलने तो दीजिये, जवाब तो देने दीजिये । . . (व्यवधान) . . .

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This is not the way. (*Interruptions*).

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: He is misleading the House. (*Interruptions*). Madam, what is this? (*Interruptions*).

SHRI MD. SALIM: Madam, what is this going on?

(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Salim, please sit down.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदया, (व्यवधान) . . .

श्री एस० एस० अहलुवालिया : ये इस तरह के शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हैं ? (व्यवधान) . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. (*Interruptions*). The reply is going on. Don't use the word 'nonsense'. It will not go on record. Don't use the word which we do not use in the House. It will not go on record.

श्री कल्पनाथ राय: उपसभापति महोदया, . . (व्यवधान) . .

उपसभापति : सलीम साहब, बैठिये । बैठ जाइये । . . (व्यवधान) . . .

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam.. (*Interruptions*).

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Madam... (*Interruptions*).

SHRI MD. SALIM: Madam,... (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. (*Interruptions*).

श्री एस०एस० अहलुवालिया : मैडम, अभी प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर ने कहा है कि The Minister of is talking*

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Yes, he is talk'g*.

SHRI S. S. AHLUWALIA: What is this? (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will look into the record. (*Interruption*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, is the word unparliamentary? (*Interruptions*).

श्री एस०एस० अहलुवालिया : बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: This word is unparyiamentary according to our book. I will not allow it to go on record.
मंत्री जी, आप जरा जवाब दीजिये।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदया, मैंने सभी मित्रों से कहा कि बीआई सीपी से, इंडस्ट्रियल शूगर का दाम वह तय करता है, वह एक्सपोर्ट बाडी है और गन्ने का दाम तय करता है एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन।.. (व्यवधान) ...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Is this an argument? (*Interruptions*).

श्री मोहम्मद सलीम : इसी सवाल पर शिकायत है इस पर आरग्यूमेंट नहीं हो सकता। गलत हिसाब दिखा रहे हैं वह। (व्यवधान) ...

*Expunged as ordered by the Chair.

شری محمد سلیم: اسی سوال پر شکایت ہے اس پر آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا۔ غلط حساب دکھا رہے ہیں وہ . . . " مداخلت " . . .

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It gives a wrong message to the country. (*Interruptions*).

श्री मोहम्मद सलीम : वह गलत जवाब नहीं बतायें। (व्यवधान) ...

شری محمد سلیم: وہ غلط جواب نہیں بتائیں . . . " مداخلت " . . .

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदया ये सवाल आप लोगों की तरफ से पूछे गये हैं; अगर मैं आपको गलत.. (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, he is defending the price rise. (*Interruptions*).

श्री कल्पनाथ राय : मैं आपसे कहना चाहता हूं .... (व्यवधान).... मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे मित्रों ने सवाल उठाए हैं और बीसियों-पच्चीसियों प्लोगों ने बोले हैं, उनका उत्तर देना मेरे लिए जरूरी है। शूगर का दाम ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइसिस तय करता है और गन्ने का दाम एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन तय करता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब यह नरसिंह राव जी की सरकार बनी और जसि [illegible] खाद्य मंत्री बनने का मौका मिला... (व्यवधान)... उपसभापति महोदया, 475 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के किसानों का गन्ना मिलों पर, सहकारिता की मिलों पर, प्राइवेट मिलों पर बकाया था और उसी किसानों के बकाया के सवाल को लेकर उत्तर प्रदेश में लाठी-गोली चली थी। कई किसान मर गए, हजारों किसान जेल गए। आदरणीय नरसिंह राव जी ने... (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं

कि आदरणीय नरसिंह राव जी ने कहा कि जब तक गन्ना किसानों को उनका बकाया नहीं दिया जाएगा तो वे किसान गन्ना नहीं बोएंगे । 475 करोड़ रुपए .... **(व्यवधान)** यह नहीं हो सकता । क्या बात करती हैं आप । ... **(व्यवधान)**

DR. BIPLAB DASGUPTA: The Minister is not talking sense... He is making a fool of himself. ..(*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DASS GUPTA: It is absolutely senseless.

SHRI KALP NATH RAI: You know nothing about it... (*Interruptions*).

श्री एस० एस० अहलुवालिया : किसानों के बफादार बनते हैं और किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं । ... **(व्यवधान)**

उपसभापति : अहलुवालिया जी, आप बैठ जाइए । कल्पनाथ जी, बहुत समय हो गया, सवा छः बज गया है । हम लोग पूरी एग्रीकल्चर पौलिसी गन्ने की डिस्कस नहीं कर रहे हैं । .... **(व्यवधान)**

I don't want any clapping for it Mr. Minister, you please try to confine yourself to the question put. Otherwise, it will go out of hand. The discussion and the reply will totally go out of hand. So, please confine yourself to the questions. While I have requested the Minister, I also request the Member kindly not to disturb him because if anybody disturbs him, then he will go out of hand... (*Interruptions*) I said about the discussion. I said before that the discussion would go out of hand... (*Interruptions*). I told the Minister, "The discussion will go out of hand.' So, please, don't disturb him.. (*Interruptions*) I am very serious... (*Interruptions*). Please, just a minute. I want silence in the House. I have requested the Minister to confine himself to the discussion in the House. Now, if you disturb, then I can get confused, he can get confused and you can get confused. So. please, don't do that. Let him confine himself to the questions and I request everybody not to disturb him. Otherwise, the discussion will not be in proper order. It will really go out of hand. I am telling you again... (*Interruptions*)

SHRI M. A. BABY: We are already confused.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आप यहां पर मौजूद नहीं थीं और आपके न रहने पर 25–30 माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए, अगर उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दूं तो यह उचित नहीं है ।

उपसभापति : नहीं, आप दीजिए । आप जरूर जवाब दीजिए ।

श्री कल्पनाथ राय : आपने यहां पूछा कि प्राइस क्यों बढ़ा । तो प्राईस को बढ़ाने के लिए, मैंने कहा कि शुगर का प्राईस ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राईसेज तय करता है । तो बी. आई. सी. पी. ने जो डिसाइड किया, उसको मैं सदन को नहीं बताऊं तो यह उचित नहीं है ।

उपसभापति : नहीं, आप बताइए । जो सवाल किए हैं वह जरूर बताइए । .... **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : दूसरी बात, एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राईसेज कमीशन जो किसानों के गन्ने का दाम तय करती हैं, अगर वह नहीं बताऊं तो फिर चीनी का दाम कैसे तय होगा, कौन तय करेगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने का जो प्रोडक्शन घटा उसका एक कारण यह भी था कि 475 करोड़ रुपए .... **(व्यवधान)**

उपसभापति : अभी डिस्टर्ब नहीं कीजिए ।

श्री कल्पनाथ राय : रेड्डी साहब, आप जो बात बोले हैं, 475 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया था, जिस दिन हम खाद्य मंत्री बने, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि –कल्पनाथ, पहले गन्ना किसानों का दाम नहीं दोगे तो गन्ना किसान गन्ना नहीं बोएंगे । 475 करोड़ रुपए में 460 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान हमारी सरकार ने किया, केन्द्र की सरकार के द्वारा किया गया है । ... **(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, यही सवाल है जो गन्ने का दाम.... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I told you not to disturb. He is confining... (*Interruptions*). Joshiji, please, I will not allow... (*Interruptions*). I am not allowing it... (*Interruptions*). Joshiji, please, I requested not to interrupt. You had your time. You had your discussion. You put your questions. Please, let him reply. He has not completed. This is neither a Question Hour nor a debate in a school. You made your point. He has to answer, please.

श्री कल्पनाथ राय : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये लोग इतने घंटों से सवाल पूछ रहे हैं, अगर मैं उन प्रश्नों का जवाब दे दूं तो ठीक नहीं होगा । जबसे देश आजाद हुआ, तब से कांग्रेस सरकार ने गन्ने का जो दाम दिया है, आप बताइए क्या हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने दिया है । तो जब गन्ने का दाम बढ़ेगा तो चीनी का दाम भी बढ़ेगा, वह रुक नहीं सकता । यह सच्चाई अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपकी इच्छा । हम 9 रुपए प्रति किलों के हिसाब से चीनी सारे हिन्दुस्तान को दे रहे हैं .... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't understand. When I told the Members not to disturb the Minister, they are doing it. It seems they don't understand my language. I don't know which language I should speak.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदया, 9 रुपए 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हिंदुस्तान की करोड़ों-करोड़ गरीब जनता को चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से यह सरकार दे रही है । आदरणीय रेड्डी जी, मैं आपसे पूछता हूं कि यह जिम्मेदारी किसकी है ? यह जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है । बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार, बंगाल की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरसरकार, महाराष्ट्र की सरकार, केरल की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, इन सारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम जो चीनी दे रहे हैं, वह चीनी वे अपनी सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से आम जनता को पहुंचाएं । मैं कहना चाहता हूं कि हम कास्ट आफ प्रोडक्शन से ढाई-तीन रुपए कम दाम पर गरीब जनता को चीनी मुहैया कराते हैं ।

आदरणीय जोशी जी, आप तो प्रोफेसर रहे हैं । कल मैंने आपको सुना । जैसे ही मैं आया जोशी जी बोलने लगे । हमारे आदरणीय मित्र क्या-क्या बोले । मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रोफेसर रहने के नाते कुछ शिष्टाचार, अनुशासन आप में भी होना चाहिए । आपने सारे जीवन छात्रों को पढ़ाया है । आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा, आप अपने प्रति व्यवहार हमसे चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप भी हमारे साथ करें । यह संसद हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है और जो संविधान है वह हमारी गीता है । इस देश के सबसे बड़े मंदिर में हम संविधान रूपी गीता हाथ में लेकर कसम खाते हैं । यहां पर हम लोग बहस करें, जितनी भी बिटर बहस करना चाहें करें लेकिन ऐसा काम न करें कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र भी समाप्त हो जाए । एक ही बात में आपको सुनाऊंगा—

"कमज़र्फ को साकी जाम न दे,
तौहीन न कर पैमाने की,
वह पी लेगा फिर बहकेगा,
शामत होगी पैमाने की"

तो रेड्डी जी आपसे निवेदन है कि ऐसा काम मत कीजिए । आपने एक बार भी प्रशंसा नहीं की कि इस सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों का 475 करोड़ रुपया दे दिया । आपने एक बार भी नहीं कहा कि 12 रुपए क्विंटल का दाम बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए हिन्दुस्तान के किसानों को नरसिंहराव जी की सरकार ने दे दिया । ... (**व्यवधान**)

SHRI SIKANDER BAKHT: Will you request him to come down to *chini* from *gaana*? Let him come down to *chini*.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदया, हमारे मित्र राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के मंत्री थ और हमारी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

भी मुख्य मंत्री रहे है, आप सरकार के मंत्री थे एक साल तक किसानों को दाम नहीं दिया गया ।.... **(व्यवधान)**। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता । लेकिन जो सरकार की बाध्यताएं हैं, जो सरकार के कंपलांस हैं, उनको आप भी जब सरकार में थे तो चाहते हुए भी आप नहीं दे पाए । लाठी चली, गोलियां चलीं । हजारों लोग मारे गए । हजारों लोग जलाए गए, किसान मारे गए देवरिया में राम टावेला में क्या हुआ ? राम कोला में गोली चली .... **(व्यवधान)**

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam, I am on a point of order.

उपसभापति : कल्पनाथ जी बैठिए, एक प्वाइंट आफ आर्डर है । .... **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is for me to decide. (*Interruptions*) I do not understand why you people get up. Sikander Bakht Sahib, can you control your Members? (*Interruptions*).

SHRI M. A. BABY: Madam, my point of order is that the whole House was exercised over a scandal, and in its wisdom the Business Advisory Committee decided that there will be a Short Duration Discussion, and Members have raised many relevant points, and the Minister is expected to reply to the points raised. If the Minister is for having this kind of a cultural programme, perhaps, the Constitution Club can organise a ticketed programme in the Mavalankar Auditorium, but we expect the Minister to reply to the questions that we have raised. Therefore, from the Chair, kindly direct the Minister to address the points raised by the hon. Members in the discussion. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to deal with his point of order. I may not agree with whatever language he has used, but what he tried to say and the others are also objecting is बीच में लोग बोल रहें हैं कि उन्होंने जो प्वाइंट उठाए हैं उनका जवाब दें, दीजिए रिपिटिशन मत कीजिए, बहुत लेट हो गया ।

We have other busienss also.

आप प्वाइंट वाइज प्वाइंट जवाब दे दीजिए। .... **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदया, हमारे मित्र लोगों ने सवाल उठाया मालेसेज के डिकंट्रोल का सवाल उठाया । मैं कहना चाहता हूं कि मालेसेज को डिकंट्रोल करने के लिए आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने, शिब्बनलाल सक्सेना जी ने, केदार सिंग बसंत दादा पाटिल सारी जिन्दगी संघर्ष करते रहे । मालेसेज को डिकंट्रोल करके नरसिंह राव जी ने उस उद्योग को इतना जानदार बना दिया है कि जिससे भविष्य में भारत की जनता को लाभ मिलेगा ।

श्रीमती सुषमा स्वराज मेरा प्वाईंट आफ आडर है...

श्री कल्पनाथ राय : प्वाइंट आफ़ आर्डर क्या है, कोई नहीं है । मैं आपसे कहना चाहता हूं ....

श्री राज नाथ सिंह : मोलेमिस के डी-कंट्रोल करने से मिल मालिकों को धनवान बना दिया है आपने । **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । जब इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं तो आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं क्या करूंगा । **(व्यवधान)** सवाल उठाया है जवाब दे रहा हूं । **(व्यवधान)**

उपसभापति : चेयर आपकी मदद कर रही है इसलिए सबको चुप करा रही हूं । मैं आपकी पूरी बदद कर रही हूं । इसलिए मैंने आप से कहा कि अगर आप उन सवालों का प्वाटेंब जवाब देंगे तो मैं दूसरों को चुप करा सकती हूं । अगर बहुत ज्यादा लम्बा बोलेंगे तो मुश्किल होगी हाउस में ।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदया, यह सवाल हमारे विद्वान जयपाल रेड्डी जी ने उठाया था । उनकी बात का जवाब मैंने दे दिया है । अगर ये लोग मोलेसिस के डीकंट्रोल के लिए संघर्ष नहीं करते तो किसानों के हित में ... (**व्यवधान**) जब चीनी उद्योग की बात आप करते हैं तो चीनी उद्योग की बात करना, गन्ना पैदा करने वाले किसान की बात करना, गन्ना मिल मालिक की बात, इसका उपभोग करने वालों की बात .... (**व्यवधान**)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, still he is not... (*Interruptions*)... What he is say about molasses is... (*Interruptions*)...

श्री जनार्दन यादव : शुगर स्कैंडल में क्या हुआ ? .... (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय जनार्दन यादव जी आप बिहार से आते हैं । कितना बढ़िया प्रशासन वहां चल रहा है आपको इसकी जानकारी है .... (**व्यवधान**) जब इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं । (**व्यवधान**) मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं । (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन यादव : शुगर स्कैंडल के बारे में क्या हुआ वह बताइये । कौन जिम्मेदार है (**व्यवधान**)

उपसभापति : कल्पनाथ राय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप रिपीट न करें । क्योंकि अगर आपने एक दफा बोल दिया तो आप उम्मीद करिये कि मेम्बर समझ गये होंगे फिर दूसरे प्वाइंट पर आइये । (**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त : मेरा सिर्फ यह कहना है कि बात को महदूद रखिये अक्तूबर, 93 से लेकर अब तक, मेहरबानी होगी ।

रात का न जिक्र कर रात तो गुजर गई,
ए सहर तू यह बता रोशनी किधर गई ।

मेहरबानी करके अपनी बात को अक्तूबर से लेकर अब तक महदूद रखिये। (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, no more interruptions, no more suggestions, please. Enough. I am not allowing any... (*Interruptions*)...

श्री कल्पनाथ राय : : उपसभापति महोदया, आखिरी बात कह कर मैं खत्म करूंगा । सिकन्दर बख्त जी जी ने कहा है .... (**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराज : कौन जिम्मेदार है यह बताइये ।.... (**व्यवधान**)....

श्री कल्पनाथ राय : जब सरकार में आप होंगे तो सरकार.... (**व्यवधान**) एक मिनट मेरी बात सुनिये ।... (**व्यवधान**) हमारी बात सुन लीजिये । जब आपकी बात हमने सुन ली तो आप अपने मेंबरों से कहें कि वे मेरी बात भी सुनें । मेरा कहना है कि यह राजनीति नहीं चलेगी कि मीठा मीठा गप कडवा कडुवा थू, यह नहीं चलेगा । जब आप सरकार में होंगे तो गन्ना जलाया जायेगा । जब आप सरकार में होंगे, जब आप सारे विरोधी दलों के लोगों की सरकार होगी तो गन्ना जलाया जायेगा और जब आपकी सरकार प्रदेश में होगी तो किसानों पर लाठी, गोली चलायी जायेगी ।... (**व्यवधान**)...एक ही बात.

SHRI SIKANDER BAKHT: He is going beyond all limits. This is absolutely unbearable. We cannot tolerate this* We are walking out against this*

(At this stage some hon. Members left the chamber)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, as the Minister has not replied to the points raised by the hon. Members, we are walking out.

(*At this stage some hon. Members left the chamber*)

*Expungged as ordered by the Chair.

श्री कल्पनाथ राय : आपको मेरी बात सुननी होगी । आप लोग जब सरकार में होंगे तो लाठी गोली चलेगी । आप जब सरकार में होंगे तो किसानों का गन्ना जलवायेंगे । जो सरकार अच्छा काम कर रही है, उस सरकार के खिलाफ इस तरह की बातें उचित नहीं । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता करता हूं । धन्यवाद ।

श्री कैलाशनारायण सारंग : "जिनको न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे कमज़र्फ को महफिल में बुलाते क्यों हो ।

THE COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL, 1993

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): Madam, I move.

That the following amendments made by the Lok Sabha in the Coir Industry (Amendment) Bill, 1993, be taken into consideration, namely:—

ENACTING FORMULA

1. Page 1, line 1,—

for 'Forty-fourth' *substitute* 'Forty-fifth'

CLAUSE-1

2. Page 1, line 3,—

for '1993' *substitute* '1994'

The question was put and the motion was adopted.

SHRI M. ARUNACHALAM: Madam, I move:

That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to.

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know it is quarter to seven o'clock now. The Minister of Health is here for giving the reply. If Members want, we can ask him to reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, the Ordinances are being passed, and it will be reported... (*Interruptions*).

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, Special Mentions are there. M

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the Special mentions are pending. Now I will call the names for the Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Insult and humiliation to the Chairman of Scheduled Castes Scheduled Tribes Commission

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभापति महोदया' दलितों पर होने वाले अत्याचारों की घटनायें आये दिन अखबारों में छपती हैं और अक्सर उन मसलों को सदन में भी उठाया जाता है । लेकिन जब भी हम लोग सरकार से यह पूछते हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचें हैं तों बहुत ही दभ के साथ एक बात बार-बार सरकार की ओर से कही जाती है कि हमने अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लिये एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया । यह बात एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर सरकार की ओर से गिनाई जाती हैं । लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुये लोगों से यह पूछना चाहती हूं कि यदि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष स्वयं अत्याचार के शिकार हो जायें तो वह किस के दर पर जाकर गुहार करें? इस समय यह मसला सदन में उठाते समय मेरे हाथ में अनसूचित जाति और